RNI Reg. No. CHHBIL/2020/80139
Volume- 03 Issue-12
Bilingual Monthly (Hindi-English)

November 2023
Price- RS 20
32 Pages

Lok Shakti

लोक शक्ति

डीपफेक टेक्नोलॉजी के खतरे

रोज करें 5 एक्सरसाइज

आर्म पर जमा फैट हो जाएगा गायब

उम्र बढ़ने के साथ शरीर पर चर्बी जमना महिलाओं के लिए एक बड़ी समस्या होती है. बढ़ते वजन के कारण वे अपने पसंदीदा कपड़े नहीं पहन पातीं और जल्दी थकान भी महसूस करने लगती हैं. खासतौर पर महिलाओं के लिए अपने हाथ के लटकते फैट को कम करना सबसे बड़ा काम लगता है. कई महिलाओं के पास जिम जाने का वक्त नहीं होता है और ना ही घर में किसी तरह का एक्सरसाइज मशीन ही होता है. ऐसे में निराश होने की जरूरत नहीं, आप घर पर कुछ सिंपल एक्सरसाइज की मदद से अपने हाथों को टोन्ड और फिट बना सकती हैं.

पहली एक्सरसाइज – सबसे पहले आप सीधा खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को बॉडी से करीब एक बित्ते की दूरी पर हटाकर रखें. अब हाथों को एक साथ ऊपर ले जाएं और ताली बजाकर दोबारा पहले पोजीशन में आ जाएं. ऐसा एक मिनट तक करें.

दूसरी एक्सरसाइज – दोनों हाथों की कोहनियों को 90 डिग्री पर फोल्ड करें. अब मुट्ठी बांधकर हाथों को एक बार सामने लाएं और एक दूसरे से सटाएं और फिर पहले पोजीशन में आ जाएं. ऐसा आप लगातार एक मिनट तक करें फिर रिलैक्स करें.

तीसरी एक्सरसाइज – अब दोनों हाथों को सीधा करें और उंगलियों को सीधा करते हुए पीछे नीचे की तरफ सीधा करें. अब तीन बार दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए आगे सीने के पास आगे पीछे करें और फिर चार बोलते हुए नीचे पीछे की तरफ झटककर ले जाएं. ऐसा एक मिनट तक करें.

चौथी एक्सरसाइज – अब दोनों हाथों को दोनों तरफ पंख की तरह सीधा कर लें और एक बार उठाएं और एक बार थोड़ा नीचे की तरफ बेन्ड करें. ऐसा आप 1 मिनट तक करें.

पांचवीं एक्सरसाइज – अब दोनों हाथों को कोहनियों से बेन्ड करें और आकाश की तरफ प्वांइट करें. अब हाथ को एक मिनट तक ऊपर नीचे करें. हफ्तेभर में आपके हाथ टोन्ड होने शुरू हो जाएंगे. धीरे धीरे आप अपनी क्षमता के अनुसार व्यायाम के समय को बढ़ाकर 3 से 4 मिनट तक ले जाएं. आप चाहें तो दोनों हाथों में पानी के बोतलों को लेकर भी ऐसा कर सकती हैं.

Lok Shakti

EDITOR-IN-CHIEF Premendra Agrawal
EXECUTIVE EDITOR Rajesh Agrawal
MANAGING EDITOR Mr. Subhash
GROUP CREATIVE EDITOR Anjana
CHIEF ART DIRECTOR Deepika
FOREIGN EDITOR(US) Jamuna
CHIEF DESIGNER Vineeta Agrawal

RNI: CHHBIL/2020/80139

BUSINESS OFFICE

CHIEF EXECUTING OFFICER Satyabhama Agrawal
GENERAL MANAGER Vinod Agrawal
PUBLISHER Premendra Agrawal
MARKETING DIRECTOR Mr. Subhash
PHOTOGRAPHER Pawan Kumar
DIGITAL Tejas Agrawal
CHIEF PHOTO RESEARCHER Krisha

HEAD OFFICE

LOK SHAKTI, Agrasen Marg
Ramsagarpara, Raipur,
Chhattisgarh - 492001 (INDIA)
Whatsapp : 9926022174
e-mail: lokshakti.india@gmail.com

Printed and published by Premendra Agrawal
Editor: Premendra Agrawal.
Printed at Commercial Services
Agrasen Marg, Ramsagarpara, Raipur (CG).
Published from LOK SHAKTI, Agrasen Marg
Ramsagarpara, Raipur (CG).

YEAR : 04; ISSUE : 02
Published for the Month of November , 2023
Released on November, 2023

Total no. of pages 32, including Covers

SCAN AND SHARE

Read Lok Shakti on your
smart phone instantly.
Point your phone's scanner on the
code above and align it in the frame.
You will be guided instantly
to www.lokshakti.in.

NAVIGATOR

05 COVER STORY
डीपफेक से निपटेगी सरकार

07 आदिवासी कल्याण पीएम जनमन अभियान
08 देश, ग्रेटर ग्लोबल गुड के लिए एक साथ आएं
09 देवस्थलों पर भक्तों का सैलाब

02 रोज करें 5 एक्सरसाइज
10 Khalistan पर जनमत संग्रह फेल
11 सेमीकंडक्टर निर्माण
12 Education
13 सामुद्रिक सुरक्षा बैठक
14 भारत में आतंक का खूनी खेल
15 30 औद्योगिक गलियारे
16 भारत पोस्ट-प्रोडक्शन उद्योग का केंद्र
18 भारत की जीवंत विरासत
19 हिंद-प्रशांत क्षेत्र
19 भारत की जैव-अर्थव्यवस्था
20 रामलला का भव्य मंदिर तेजी से हो रहा तैयार
21 विजय दिवस
22 Economy\
23 औद्योगिक प्रदूषण आपदा
24 भूख के लिए पीएम मोदी का विजन:
25 4 ट्रिलियन डॉलर के पार हुई देश की जीडीपी
26 भारत आटा
27 Tech News
28 भारत-बांग्लादेश सहयोग

Message from Executive Editor's

We welcome you to our monthly magazine! You will find contents from across sectors including Politics, Education, Health, Economics among others. We have a great emphasis on Opinions, News & Analysis along with hints and Events from across the globe.

We want our publication to be valuable for you so please, do share your feedback and suggestions to help us improve. We have signed you up for our monthly magazine in the hopes that you will find great value in its content. Lok Shakti's publication comes with promise of great growth and change.

With each passing year, Interests and taste change, economies and leadership rise and fall, children age and grow … in truth it sees perhaps the most change of all.

…The media is simply a tool, and it's our job to help you use it in the way that's right for you as well as for the country and the world.

Sincerely,
Rajesh Agrawal
Executive Editor

नकली वीडियो की समस्या गंभीर

नकली वीडियो की समस्या गंभीर है। अब AI से, DEEP FAKE से ये खतरा और भी बढ़ गया है। चुनाव के दौरान शिवराज सिंह को बदनाम करने के लिए अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता का गलत इस्तेमाल किया गया, KBC जैसे बड़े शो की विश्सनीयता का बेजा इस्तेमाल हुआ, ये खतरनाक प्रवृत्ति है। जब तक चुनाव आयोग के पास शिकायतें पहुंची, पुलिस में FIR हुई तब तक काफी नुकसान हो चुका था। ये तो कुछ मिसालें हैं। आजकल सबके फोन में नकली वीडियो हर रोज़ आते हैं लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें गंभीरता से नहीं लेते। जो गंभीरता से लेते हैं, उनके पास इन वीडियो की सच्चाई जानने का कोई तरीका नहीं है।

फेक वीडियो का कैसे दुरूपयोग हो सकता है, इसका उदाहरण मध्य प्रदेश के चुनाव में हुआ। चुनाव के दौरान फेक वीडियो का खूब इस्तेमाल हुआ। कांग्रेस और बीजेपी ने इसको लेकर चुनाव आयोग में एक दूसरे के खिलाफ खूब शिकायतें कीं। वोटिंग खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान नकली, झूठे वीडियो दिखाए और जनता को गुमराह करने की कोशिश की। दरअसल, बीजेपी ने झूठे प्रचार और गलत तरीकों से प्रचार के करीब दो दर्जन शिकायतें की हैं, इनमें ज्यादातर शिकायतें उन वीडियो की है, जो दूसरे वीडियो पर नकली आवाज़ और ग्राफिक्स सुपरइंपोज करके बनाए गए हैं। इस तरह के कई वीडियो मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया के जरिए खूब फैलाए गए।

सारे वीडियो को वैरिफाई कर पाना असंभव है। दूसरी बात ये है कि दो तीन साल पहले एक नकली वीडियो तैयार करने में दो-तीन दिन लग जाते थे, उसके लिए बहुत सारी हाई डेफिनेशन फुटेज की जरुरत होती थी, अब तो एक से एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। चार-पांच घंटे में फर्जी वीडियो तैयार हो जाते हैं। किसी वीडियो पर नकली आवाज़ लगाना, लिप सिंक मैच करना तो और भी आसान हो गया है।

नकली वीडियो से रातों रात किसी की बदनामी हो सकती है, लोगों की भावनाएं भड़काई जा सकती हैं, इसलिए ये समाज के लिए बड़ा खतरा है। इसका एक और पहलू है। वो ये कि अगर किसी नेता का वीडियो असली हो, वो रिश्वत लेते भी पकड़ा जाए, सिफारिश करते उसका वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, तो वो बड़ी आसानी से कह देगा कि ये वीडियो नकली है। फॉरेंसिक जांच करवा लो, जांच होते होते, रिपोर्ट आते-आते महीनों लग जाएंगे। अगर रिपोर्ट खिलाफ आई तो रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए जाएंगे, इसलिए इस खतरे को समझना जरूरी है। साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से इसके बारे में लोगों को जागरूक करना ज़रुरी है,और हम सबको सावधान रहना है कि बिना वैरिफाई करे, किसी भी वीडियो को forward न करें और जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, fake video और deep fake पर, AI पर, नकली होने का, फेक होने का, फर्जी होने का ठप्पा लगाना पहला कदम है। जैसे-जैसे technology और आगे जाएगी, ये खतरा और बढ़ेगा और हम सबको और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी।।

इस पूरे मसले में मीडिया की जिम्मेदारी बहुत अहम है। हम लोगों को INFORMED रखें, AI को और CHAT GPT को विश्वसनीयता देने की बजाए जहां-जहां इसका इस्तेमाल करें उसे फेक बताना न भूलें। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। टेक्नोलॉजी का बेजा इस्तेमाल न हो। कोई किसी की इज्जत उछालने के लिए फर्जी वीडियो और DEEP FAKE का इस्तेमाल न कर पाए।

डीपफेक से इस तरह निपटेगी सरकार, जानें क्या है प्लान?

डीपफेक वीडियो और वीडियो दोनों रूप में हो सकता है। इसे एक स्पेशल मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके बनाया जाता है जिसे डीप लर्निंग कहा जाता है। डीप लर्निंग में कंप्यूटर को दो वीडियोज या फोटो दिए जाते हैं जिन्हें देखकर वह खुद ही दोनों वीडियो या फोटो को एक ही जैसा बनाता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे बच्चा किसी चीज की नकल करता है। इस तरह के फोटो वीडियोज में हिडेन लेयर्स होते हैं जिन्हें सिर्फ एडिटिंग सॉफ्टवेयर से ही देखा जाता है। एक लाइन में कहें तो डीपफेक, रियल इमेज-वीडियोज को बेहतर रियल फेक फोटो-वीडियोज में बदलने की एक प्रक्रिया है। डीपफेक फोटो-वीडियोज फेक होते हुए भी रियल नजर आते हैं।

डीपफेक टेक्नोलॉजी के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार सख्त हो गई है। सरकार जल्द ही कड़े कदम उठाने जा रही है। कहा जा रहा है कि सरकार डीपफेक को लेकर सरकार कड़े नियम ला सकती है। जिसमें सख्स से सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से एक्शन लेने और कड़े कानून बनाने को कहा है। कंपनिया इस दिशा में काम भी कर रही हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बैठक के बाद केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीपफेक को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा-सरकार रेगुलेशन लाने पर विचार कर रही है। डीपफेक से निपटने जल्द ही नियम बनाए जाएंगे।

डीपफेक पर एक्शन

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, 'सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी डीपफेक का पता लगाने और एक्शन की बात कही है। कंपनियां 'डीपफेक' का पता लगाने, इससे निपटने, इसकी जानकारी देने और यूजर्स में जागरूकता बढ़ाने पर सहमत हुई हैं। हम आज से ही ड्राफ्ट रेगुलेशन तैयार करने शुरू कर देंगे और कुछ ही समय में हमारे पास डीपफेक से निपटने के लिए नए नियम होंगे।'

डीपफेक लोकतंत्र के लिए खतरा

केंद्रीय मंत्री ने डीपफेक को लोकतंत्र के लिए नया खतरा बताया और कहा कि अगली बैठक दिसंबर से पहले हफ्ते में होगी। आज जो भी फैसले लिए गए हैं, अगली बैठकर में उनपर आगे की बातचीत की जाएगी। ड्राफ्ट रेगुलेशन में क्या-क्या शामिल करना है, इस पर विचार किया जाएगा।

क्या है डीपफेक विवाद

हाल ही में बॉलीवुड एक्टर-एक्ट्रेस को निशाना बनाने वाले कई डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए हैं। जिसको लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। इस तरह के नकली कंटेंट पर कई तरह के सवाल उठाए गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गरबा खेलते हुए उनका भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो हो रहा, जबकि उन्होंने कभी गरबा खेला ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने इसे खतरनाक चीज बताया और गंभीरता से लेने को कहा।

हां हम आपको बताएंगे कि आप डीपफेक वीडियो की पहचान कैसे कर सकते हैं और इसे कैसे बनाया जाता है.

डीपफेक एक चिंता का विषय: PM Modi

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस मामले पर जागरुकता फैलाने के लिए कहा है ताकि इससे और ज्यादा लोगों को फंसने से बचाया जा सके. पीएम मोदी ने कहा कि डीपफेक का बढ़ता खतरा एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है और सभी के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा कर सकता है.

आखों के मूवमेंट ध्यान से देखें

डीपफेक यानी ये एक तरीके से वीडियो को रिक्रिएट करना होता है. जिसमें डीपफेक क्रिएटर लोगों की जिंदगी पर असर डालने वाली वीडियो क्रिएट करते हैं.

डीपफेक वीडियो की पहचान करने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो में शख्स की आखों को देखें अगर आपको आवाज, एक्सप्रेशन और स्टेबल आखें दिखती हैं तो ये डीपफेक वीडियो है. दरअसल असली वीडियो में आंखों के मूवमेंट नॉर्मल और आवाज के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं.

कलर्स का आपस में मेल ना खाना

जो डीपफेक वीडियो होते हैं उन वीडियो में आपको कलर और लाइटिंग दोनों ही अटपटी सी दिखेगी. डीपफेक क्रिएटर्स वीडियो में सही लाइटिंग और कलर कॉपी नहीं कर पाते हैं. इसलिए वीडियो में शख्स के चेहरे पर ध्यान देना चाहिए.

कॉन्ट्रास्ट ऑडियो क्वालिटी: डीपफेक वीडियो में AI जेनरेटेड ऑडियो होता है. विजुअल कंटेंट में ऑडियो क्वालिटी चेक करें. ऐसी वीडियो में बॉडी शेप अलग-अलग होता है, फेशियल मूवमेंट अलग-अलग होते हैं.

एक वीडियो में दिखाया गया कि शिवराज सिंह कैबिनेट की मीटिंग के दौरान मंत्रियों और अफसरों से कह रहे है कि 'जनता बहुत नाराज है.. बीजेपी भारी अंतर से हार सकती है...इसलिए कुछ भी करो...हर गांव में जाओ, बूथ पर जाओ...जो करना है करो...अभी वक्त है...सब ठीक करो...मैनेज करो...' असली वीडियो चुनाव के एलान से पहले शिवराज सिंह चौहान की आखिरी कैबिनेट मीटिंग का है। वीडियो असली था, लेकिन इसमें आवाज शिवराज सिंह चौहान की नहीं है। चौहान की आवाज की हुबहू नकल करके इसे वीडियो पर सुपर इंपोज किया गया। इस वीडियो को जिन व्हॉट्सऐप ग्रुप्स के जरिए फैलाया गया, उनकी शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने जांच करके इस तरह के वीडियो को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटवाया। इस तरह के वीडियो कांग्रेस से जुड़े लोगों की तरफ से सर्कुलेट किए गए। ऐसे दर्जनों वीडियो बनाए गए।

'कौन बनेगा करोड़पति' की ओरिजनल क्लिप से छेड़छाड़ की गई। होस्ट और कंटेस्टेंट की आवाज़ बदलकर सारा कटेंट बदल दिया गया। इस वीडियो से ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि शिवराज सिंह सिर्फ घोषणाएं करते हैं, उन पर अमल नहीं करते। कौन बनेगा करोड़पति शो के होस्ट अमिताभ बच्चन थे, लेकिन आवाज सबकी नकली थी। आवाज सुपरइंपोज करके, ग्राफिक्स डालकर ऐसा दिखाने की कोशिश की गई जैसे वाकई में 'कौन बनेगा करोड़पति' में सवाल पूछा गया और शिवराज सिंह चौहान को घोषणा मुख्यमंत्री बताया गया। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे मध्य प्रदेश में खूब सर्कुलेट किया। 'कौन बनेगा करोड़पति' को टेलीकास्ट करने वाली कंपनी सोनी टीवी को सफाई देनी पड़ी जिसमें कहा गया कि ये नकली वीडियो है, होस्ट और कंटेस्टेंट्स की आवाज़ से छेड़छाड़ की गई है, साइबर क्राइम सेल में शिकायत की गई है। सोनी टीवी ने लोगों से अपील की कि इस तरह के वीडियो शेयर न करें। इसी तरह मशहूर एक्टर कार्तिक आर्यन को भी इस तरह के गुमराह करने वाले एक नकली कैम्पेन में लपेट लिया गया। कांग्रेस के ब्लू टिक वाले किसी समर्थक ने कार्तिक आर्यन का एक वीडियो शेयर कर दिया और उसके साथ कैप्शन लिखा कि अब तो कार्तिक आर्यन भी कांग्रेस का समर्थन करने लगे हैं। चूंकि कार्तिक आर्यन मध्यप्रदेश के ही रहने वाले हैं, इसलिए जानबूझकर उनका वीडियो इस फर्जी कैम्पेन के लिए इस्तेमाल किया गया। इस वीडियो की खास बात ये थी कि इसमें कांग्रेस का चुनाव निशान पंजा भी लगाया गया था। कार्तिक आर्यन ने अगले ही दिन स्पष्टीकरण जारी कर दिया और कहा कि जिस वीडियो से छेड़छाड़ कर सियासत की जा रही है वो तो एक OTT प्लेटफॉर्म का एड है, जिसे डॉक्टर्ड करके कांग्रेस का विज्ञापन बना दिया गया।

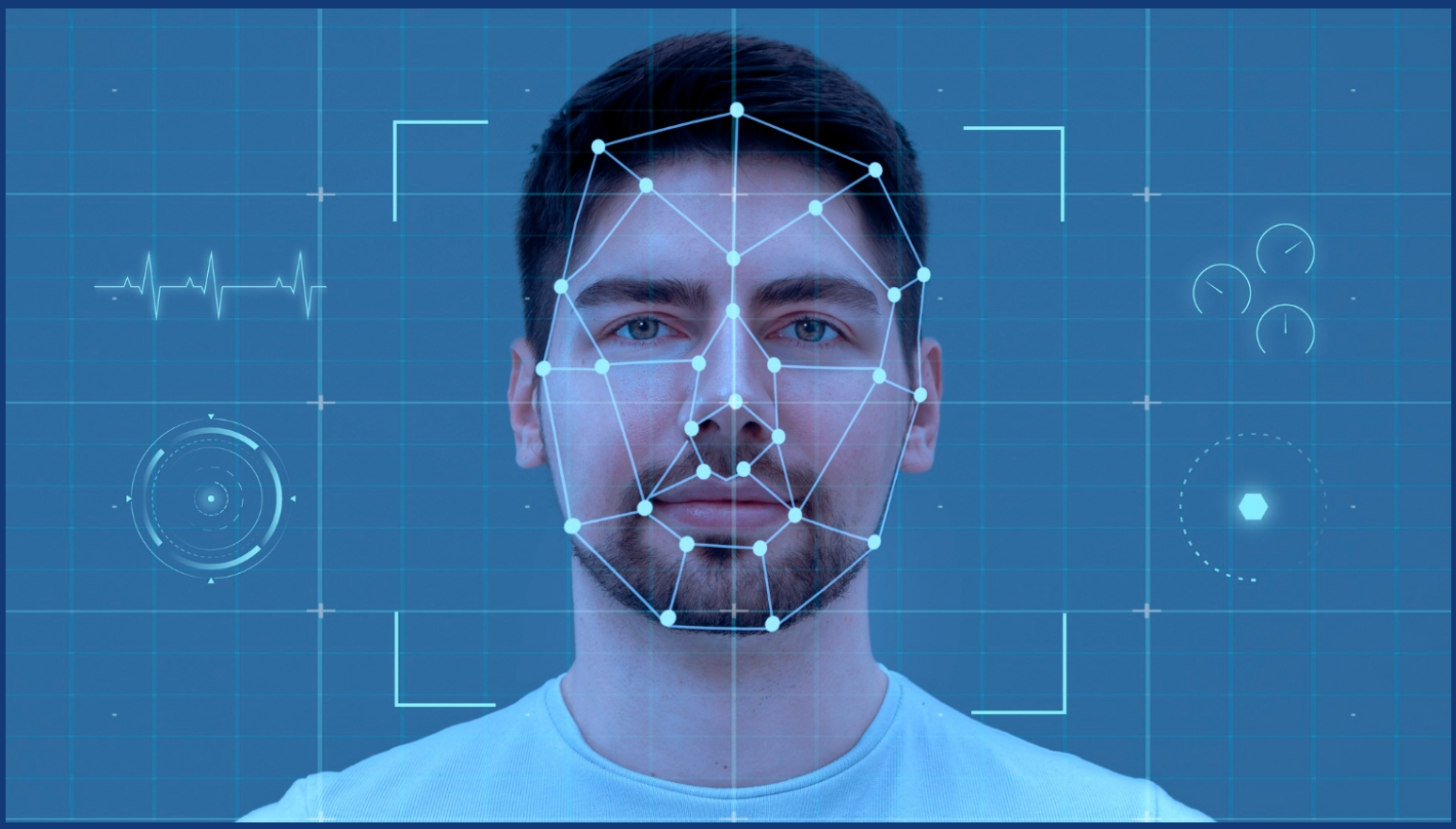

आदिवासी कल्याण के लिए पीएम जनमन अभियान बुनियादी सुविधाओं पर खर्च होंगे 24 हजार करोड़ रुपये

जो विकास यात्रा में पीछे छूट गए हैं और जंगलों में सुदूर व दुर्गम बस्तियों में रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी पहल की है। 15 नवंबर, 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को उनके जन्मस्थान झारखंड के खूंटी में श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान यानी पीएम जनमन अभियान (पीएम पीवीटीजी मिशन) की शुरुआत की। इस अभियान के तहत अति पिछड़े जनजातियों के कल्याण और पिछड़े आदिवासी इलाकों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 24 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प का एक प्रमुख आधार पीएम जनमन अभियान है। उन्होंने कहा कि मोदी हिम्मत करके निकला है आदिवासी न्याय अभियान लेकर। आजादी के बाद कई दशकों तक आदिवासी समाज को नजरअंदाज किया गया। बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने आदिवासी समाज के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया और उनके लिए अलग बजट का आवंटन किया। आज आदिवासी कल्याण का बजट पहले की तुलना में 6 गुना बढ़ाया गया है।

आदिवासियों में भी सबसे पीछे रह गए आदिवासियों के कल्याण का लक्ष्य

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि पीएम जनमन के तहत सरकार आदिवासी समूहों और आदिम जनजातियों तक पहुंचेगी, जिनमें से अधिकांश अभी जंगलों में निवास करते हैं। पहले की सरकारें सिर्फ आंकड़ों को जोड़ने का काम करती थीं, लेकिन मैं आंकड़ों को नहीं, जिंदगियों को जोड़ना चाहता हूं। इस लक्ष्य के साथ पीएम जनमन योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जैसे पिछड़ों में भी अति पिछड़े होते हैं वैसे ही आदिवासियों में भी सबसे पीछे रह गए आदिवासी हैं। देश में इनकी संख्या लाखों में है। इन सबसे पिछड़े आदिवासियों को आजादी के 75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हैं। ऐसे अति पिछड़े आदिवासियों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस योजना के तहत झारखंड के आदिवासी समुदाय के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

अती पिछड़े आदिवासियों के कल्याण और मूलभूत सुविधाओं के विकास पर जोर

इस मिशन के तहत पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक इन जनजातियों की बेहतर पहुंच बनाने और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं और जरूरतों को पूरा करने काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिशन के जरिए 17 नवंबर, 2023 को विधानसभा चुनाव में वोट डालने जा रहे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जनजातियों को भी बड़ी सौगत दी है।

देश के 22,544 गांवों के 75 आदिवासी समुदायों को मिलेगा योजना का लाभ

गौरतलब है कि मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM PVTG Mission) अपनी तरह की अनोखी पहल है। इस मिशन के तहत देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 220 जिलों के 22,544 गांवों में रहने वाले 75 आदिवासी समुदायों और आदिम जनजातियों को शामिल गया है,जिनकी आबादी 28 लाख है।

देश, ग्रेटर ग्लोबल गुड के लिए एक साथ आएं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वॉयस ऑफ़ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी में बदलते विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाला अनोखा मंच है। वॉयस ऑफ़ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के शुरुआती सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भौगोलिक रूप से ग्लोबल साउथ तो हमेशा से रहा है। लेकिन उसे इस प्रकार से आवाज पहली बार मिल रही है। और ये हम सभी के साझा प्रयासों से संभव हुआ है। हम 100 से ज्यादा अलग-अलग देश हैं, लेकिन हमारे हित समान हैं, हमारी प्राथमिकताएं समान हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मानता है कि नई टेक्नॉलॉजी, नॉर्थ और साउथ के बीच दूरियां बढ़ाने का नया स्रोत नहीं बनना चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के युग में, टेक्नॉलॉजी को जिम्मेदार तरीके से उपयोग में लाने की बहुत जरूरत है। इसको आगे बढ़ाने के लिए, भारत में अगले महीने AI ग्लोबल पार्टनरशिप समिट आयोजित की जा रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष दिसंबर में, जब भारत ने जी-20 की अध्यक्षता संभाली, तोह हमने इस फोरम में ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को आगे बढ़ाना अपना दायित्व माना। हमारी प्राथमिकता थी कि जी-20 को ग्लोबल स्केल पर समावेशी और मानव केंद्रित बनाया जाए। हमारी कोशिश थी कि जी-20 का फोकस हो – development of the people, by the people and for the people. इसी उद्देश्य से हमने इस वर्ष जनवरी में, पहली बार वॉयस ऑफ़ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। भारत के अलग-अलग राज्यों में हुई जी-20 की 200 से अधिक बैठकों में हमने ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को प्रमुखता दी। इसका नतीजा रहा कि नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में ग्लोबल साउथ के विषयों पर हमें सबकी सहमति हासिल करने में कामयाबी मिली।

उन्होंने कहा कि ये समय है जब ग्लोबल साउथ के देश, ग्रेटर ग्लोबल गुड के लिए एक साथ आएं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए हम सब मिलकर 5C's – कंसल्टेशन, कॉपरेशन, कम्यूनिकेशन, क्रिएटिविटी, और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ मिलकर आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक समृद्धि के लिए सबका साथ और सबका विकास जरूरी है। लेकिन हम सभी देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही हैं। भारत ने 7 अक्टूबर को, इजराइल में हुए जघन्य आतंकी हमले की निंदा की है। हमने संयम के साथ ही, डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। इजराइल और हमास के संघर्ष में, आम लोगों की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास जी से बात कर हमने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भी भेजी है।

देवस्थलों पर भक्तों का सैलाब

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सनातन संस्कृति को संरक्षित करते हुए निरंतर प्राचीन मंदिरों को जीर्णोद्धार कर रहे हैं। देशभर में धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालु-भक्तों का न सिर्फ सफर सुगम और सुरक्षित हो रहा है, बल्कि उन्हें तमाम सुविधाएं भी मिल रही हैं। इससे देशभर में धार्मिक पर्यटन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। देशभर के धार्मिक स्थलों पर रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नवरात्रि के दौरान मां वैष्णो देवी के दर्शन करने रिकॉर्ड 4 लाख श्रद्धालु पहुंचे। जनवरी से अब तक यहां 80 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। ऐसे में इस साल तक श्रद्धालुओं का आंकड़ा आसानी से एक करोड़ पार कर जाएगा। बीते साल 91.24 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे, जो 9 साल में सर्वाधिक है। दूसरी ओर महाकाल मंदिर में जुलाई में हेड काउंट मशीन लगने के बाद से 2.4 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। इस साल 129 करोड़ दान आया है।

आस्थास्थलों के दिव्य-भव्य बनने से तेजी से बढ़ रहा धार्मिक पर्यटन

पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने खोई हुई सांस्कृतिक विरासत को फिर से हासिल करने और उनके संरक्षण की दिशा में निरंतर उल्लेखनीय काम कर रही है। देश की आर्थिक प्रगति के लिए पर्यटन के महत्व को समझते हुए वे धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही विरासत स्थलों के विकास पर खासा जोर दे रहे हैं। धार्मिक स्थलों के विकास से आई तरक्की केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक और चार धाम आदि से समझी जा सकती है, जहां लगातार धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है। पीएम मोदी तीर्थयात्रा पर्यटन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार पर जोर दे रहे हैं। सालों से यह स्थल बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना कर रहे थे। अब पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार इन स्थलों का पुनरोद्धार कर रही है।

भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में मंदिरों को भव्य बनाने पर जोर

धार्मिक स्थलों पर अब जब सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है तो यहां पर्यटन बढ़ने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी मंदिरों को भव्य बनाने पर जोर दे रहे हैं। साल 2019 में पीएम मोदी की सरकार ने मनामा और अबू धाबी में भगवान श्रीकृष्ण श्रीनाथजी के पुनर्निर्माण के लिए 4.2 मिलियन डॉलर देने का ऐलान किया था। इसके साथ ही 2018 में उन्होंने अबू धाबी में बनने वाले पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी थी। उन्होंने 16 मई, 2022 को नेपाल के लुंबिनी में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया। यही नहीं पीएम मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों से ऐसे सैकड़ों प्राचीन वस्तुओं एवं मूर्तियों को विदेशों से वापस लाने में सफलता मिली है, जिन्हें दशकों पहले चोरी और तस्करी के जरिए विदेश भेज दिया गया था।

उज्जैन में 2.4 करोड़ और बाबा विश्वनाथ की नगरी में आए 6 करोड़ भक्त

पीएम के विजन पर चलते हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण किया गया है। इससे उज्जैन में धार्मिक पर्यटन में और ज्यादा तेजी आई है। महाकाल मंदिर में जुलाई में हेड काउंट मशीन लगने के बाद से 2.4 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। इस साल 129 करोड़ दान आया है। उधर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में इस साल अब तक 6 करोड़ से अधिक भक्त दर्शनार्थ पहुंच चुके हैं। अकेले सावन के 8 सोमवार पर ही 1.63 करोड़ पहुंचे, जो रिकॉर्ड है। देव दिवाली और नए साल तक यहां एक करोड़ से ज्यादा धार्मिक पर्यटक और पहुंच सकते हैं। धार्मिक पर्यटन के बढ़ने से आस्था स्थलों पर युवाओं को नित-नए रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं।

तिरुपति, वैष्णो देवी और चारधाम यात्रा में भक्तों के बने रहे नए रिकॉर्ड

तिरुपति मंदिर में इस साल दो करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। बोर्ड का अनुमान है कि 2023-24 में 4,385.25 करोड़ का राजस्व आएगा। बीते साल 3,096 करोड़ आया था। नवरात्रि के दौरान वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रियों की सुविधा के लिए चार अहम प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। इसमें स्काई वॉक, पार्वती भवन का पुनर्निर्माण, अटका क्षेत्र का विस्तार और भैरों घाटी में फ्री लंगर की सुविधा शुरू की गई है। वैष्णों देवी मंदिर में इस नवरात्रि ही 3.18 लाख श्रद्धालु पहुंचे। इस साल के अंत तक यहां श्रद्धालुओं का आंकड़ा आसानी से एक करोड़ पार कर जाएगा। उधर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में अब तक 50 लाख लोग पहुंच चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। बीते साल 44.32 लाख श्रद्धालु आए थे। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटूश्यामजी मंदिर में भी 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सनातन संस्कृति में अटूट और अगाध श्रद्धा का ही सुफल है कि विश्व प्रसिद्ध अयोध्या में राम लला का भव्य और दिव्य मंदिर तो बन ही रहा है, इसके साथ ही देशभर में प्राचीनतम मंदिरों के जीर्णोद्धार और मंदिर कॉरिडोर बनाने का काम भी जोरों पर है। बीते दो-तीन साल में सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ, महाकाल मंदिर कॉरिडोर बन चुके हैं। यूपी में मथुरा-वृंदावन, अयोध्या, मप्र के चित्रकूट में वनवासी रामपथ, ओरछा में रामराजा लोक, दतिया में पीतांबरा पीठ कॉरिडोर, इंदौर में अहिल्या नगरीय लोक, महू का जानापाव, असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर, बिहार में उच्चैठ भगवती स्थान से महिषी तारास्थान को जोड़ने का काम शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में महालक्ष्मी तो नासिक से त्र्यंबकेश्वर तक कॉरिडोर बन रहा है।

Khalistan पर जनमत संग्रह फेल

कनाडा के पीएम ट्रूडो की सिख वोट बैंक की राजनीति को फिर एक बार करारा झटका लगा है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में लंबे समय से प्रतीक्षित भारत विरोधी जनमत संग्रह को आधिकारिक तौर पर विफल घोषित कर दिया गया है। जनमत संग्रह के लंबे-चौड़े दावों के बावजूद इसमें मुट्ठीभर लोग ही जमा हो पाए। जनमत संग्रह का आयोजित करने वाले भारत में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन एसएफजे ने भारत की राजधानी दिल्ली को खालिस्तान के हिस्से के रूप में शामिल करते हुए एक नया विवादित नक्शा भी जारी किया। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने वाशिंगटन डी.सी. में कहा, "यह पंजाब और भारत के बीच एक युद्ध है जिसमें कब्ज़ा करने वाली सेना हिंसा का उपयोग कर रही है, जबकि सिख वोटों का उपयोग कर रहे हैं।"

हरदीप निज्जर को जहां गोली मारी, उसी गुरुद्वारे में किया गया जनमत

कनाडा के जनमत संग्रह के बारे में सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक यह सरे के उसी गुरुद्वारे में पर्याप्त पुलिस तैनाती के बीच आयोजित किया गया था, जहां जून में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दावा करते हुए आरोप लगाया था कि निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता की संभावना है। वहीं भारत सरकार ने खालिस्तानी उग्रवादी की मौत के आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया, जिसे नई दिल्ली ने पहले ही 'आतंकवादी' करार दिया था। भारत ने कनाडा से अपने उन दावों के लिए सबूत पेश करने के लिए भी कहा। ऐसा न होने पर राजनयिक को निष्कासित कर दिया था।

जनमत संग्रह में दो हजार से भी कम वोटों के चलते फ्लॉप घोषित

खालिस्तान के लिए सरे में हुए मतदान में 2000 से भी कम लोगों ने शिरकत की। स्थानीय स्रोतों से प्राप्त रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि इस बार पिछले जनमत संग्रह में भाग लेने वाले लोगों का केवल वही समूह सामने आया, जिसमें मुख्य रूप से छात्र प्रतिभागी शामिल थे। इस बार जनमत संग्रह में कोई नया समूह शामिल नहीं हुआ। जनमत संग्रह प्रक्रिया में नई भागीदारी में कमी के चलते इसे फ्लॉप करार दिया गया।इसी साल 10 सितंबर को हुए पिछले जनमत संग्रह में एक लाख से अधिक वोटों का दावा किया गया था, लेकिन वास्तविकता में मतदान महज 2398 वोट था।

देशविरोधी गतिविधियों रोकने के लिए भारत लगातार बना रहा है कनाडा पर दबाव - निराशाजनक प्रतिक्रिया मिलने के बाद अगले साल एबॉट्सफ़ोर्ड, एडमॉन्टन, कैलगरी और मॉन्ट्रियल में जनमत संग्रह आयोजित करने की चर्चा हो रही है। वहीं कभी-कभी 'सिख फॉर जस्टिस' जैसे अलगाववादी संगठन इन अनौपचारिक 'खालिस्तान जनमत संग्रह' का आयोजन करते हैं। दूसरी ओर, भारत इस मामले में लंबे समय से कनाडाई सरकार पर दबाव बना रहा है और उनसे अपने देश में स्थित व्यक्तियों और समूहों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने का आह्वान किया है, जिन्हें भारतीय कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। कनाडा में उच्चायुक्त की गिरफ्तारी पर एक लाख डॉलर इनाम देने की घोषणा की - खालिस्तान जनमत संग्रह के दूसरे चरण के समापन पर, कट्टरपंथी सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) समूह ने कनाडा में उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा की गिरफ्तारी पर एक लाख डॉलर इनाम देने की घोषणा की।

10 LOK SHAKTI

अब सेमीकंडक्टर निर्माण में होगी भारत और जापान की साझेदारी!

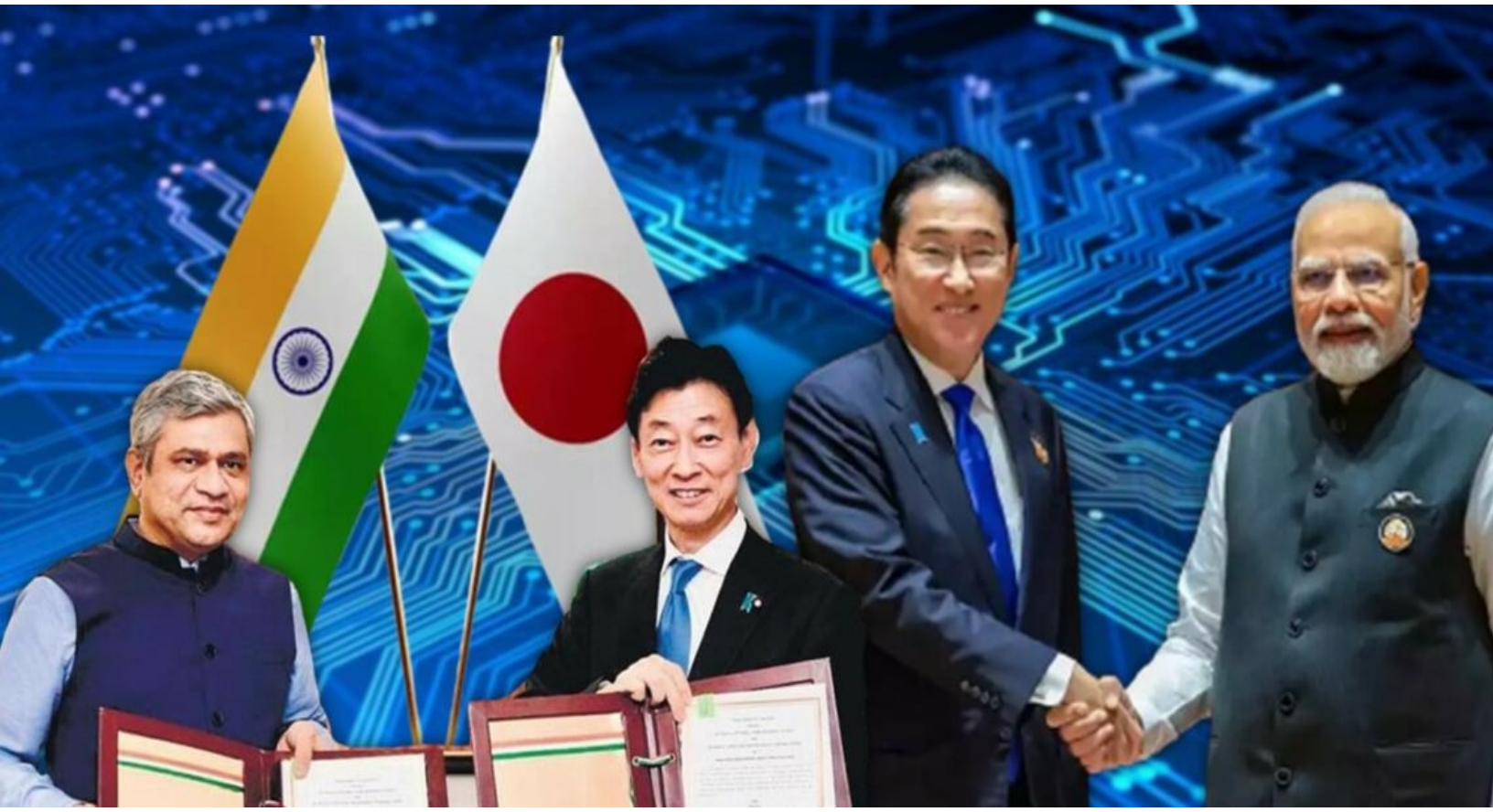

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 अक्टूबर को भारत और जापान के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन (एमओसी) को अपनी स्वीकृति दे दी। जुलाई 2023 में हस्ताक्षरित यह ज्ञापन, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास था, जो जापान-भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर केंद्रित था।

इस सहयोग ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य भारत और जापान के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देना है, जिसमें सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। दोनों देश विभिन्न उद्योगों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने में सेमीकंडक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हैं।

सेमीकंडक्टर उद्योग को अक्सर आधुनिक प्रौद्योगिकी की रीढ़ कहा जाता है, और यह सही भी है। सेमीकंडक्टर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार से लेकर स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोटिव तक उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला के कामकाज का अभिन्न अंग हैं। डिजिटल परिवर्तन के इस युग में, अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकियों की मांग कभी इतनी अधिक नहीं रही।

और पढ़ें: नई फैब परियोजनाओं के साथ भारत सेमीकंडक्टर उद्योग को ऊंचाईयों पर लेकर जाने की तैयारी कर रहा है

औद्योगिक विकास और नवाचार को गति देने में अर्धचालकों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, भारत और जापान ने सहयोग और पारस्परिक समर्थन की यात्रा शुरू की है। इस सहयोग ज्ञापन के माध्यम से, दोनों देशों का लक्ष्य सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है, तथा यह सुनिश्चित करना है कि यह लचीला और मजबूत बना रहे।

सेमीकंडक्टर उद्योग का प्रभाव दूर-दूर तक फैला हुआ है, जो विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। चाहे वह उन्नत चिकित्सा उपकरणों का विकास हो, विनिर्माण प्रक्रियाओं का स्वचालन हो, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स का विकास हो, अर्धचालक इन तकनीकी प्रगति के मूल में हैं।

सहयोग ज्ञापन, जो भारत और जापान के बीच राजनयिक और आर्थिक सहयोग का फल है, तकनीकी नवाचार के एक नए युग की शुरुआत करने की क्षमता रखता है। यह महज़ कागज़ पर किया गया समझौता नहीं है; यह दोनों देशों की एक साथ काम करने, ज्ञान और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करने और अंततः विकास और समृद्धि को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है।

NCERT: 6 से 12वीं तक इस विषय के सिलेबस में बदलाव

नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद एनसीईआरटी की किताबों में लगातार बदलाव किया जा रहा है. अब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) कक्षा 6 नसे लेकर कक्षा 12वीं तक के सामाजिक विज्ञान के सिलेबस में बदलाव करने जा रहा है. इसके लिए परिषद ने 35 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. ये कमेटी राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल और इतिहास जैसे विषयों पर शिक्षण और सीखने की सामग्री व पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने का काम करेगी.

बता दें कि 19 सदस्यों वाले एनएसटीसी को कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए जुलाई में सूचित किया गया था. जिसमें सामाजिक विज्ञान के लिए नव स्थापित पाठ्यचर्या क्षेत्र समूह (सीएजी) की अध्यक्षता आईआईटी-गांधीनगर के विजिटिंग प्रोफेसर मिशेल डैनिनो को दी गई है. बता दें कि एनएसटीसी में विभिन्न विषयों में न्यूनतम 11 पाठ्यचर्या क्षेत्र समूह निर्धारित किए गए हैं. ये सीएजी सामाजिक विज्ञान, भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) और नई शिक्षाशास्त्र और शिक्षण सामग्री के लिए पहले से गठिक हो चुके हैं.

एनसीईआरटी समिति पहले से विकसित एनसीएफ से ली गई पाठ्यपुस्तक सामग्री को अंतिम रूप देने में लगी हुई है. गौरतलब है कि एनसीईआरटी एनईपी 2020 (नई शिक्षा नीति 2020) के अनुरूप पाठ्यक्रम को भी संशोधित कर रहा है. एनएसटीसी और एनसीईआरटी को पाठ्यक्रम जमा करने के लिए 25 नवंबर 2023 तक का समय दिया गया है. यानी 25 नवबंर तक समित विषयवार सिलेबर को उपलब्ध करा देगी. वहीं एनसीईआरटी अधिसूचना में कहा गया है कि ग्रेड 3-5 के साथ निरंतरता, विषयों में अंतर-अनुशासनात्मकता और सामाजिक विज्ञान में क्रॉस-कटिंग विषयों को शामिल करने की गारंटी देने के लिए यह समूह जरूरत पड़ने पर मदद करेगा.

पहले भी किताबों में बदलाव कर चुकी है एनसीईआरटी

बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब एनसीईआरटी किसी विषय के सिलेबर में बदलाव कर रही हो. इससे पहले राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने एनसीईआरटी की किताबों से इंडिया शब्द को हटाकर 'भारत' करने के फैसला लिया था. यही नहीं 2022 में भी एनसीईआरटी ने सिलेबस में 33 फीसदी हिस्से को हटा दिया था. जिसे एनसीईआरटी ने सिलेबस रेशनलाइजेशन बताया था. जिसके तहत गुजरात दंगे, मुगल कोर्ट, इमरजेंसी, कोल्ड वॉर, नक्सली आंदोलन जैसे विषयों को सिलेबस से हटा दिया गया था. यही नहीं एनसीईआरटी ने नेशनल क्यूरीकुलम फ्रेमवर्क को भी कई बार रिवाइज किया. ये बदलाव साल 1975, 1988, 2000 और 2005 में किए गए थे. एनसीईआरटी का कहना था कि जो हिस्से उन्होंने हटाए वे नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ एलाइन होने के लिए हटाए हैं. पुराने हिस्से हटाकर नये हिस्से जोड़े गए, जिनमें जीएसटी, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ आदि जैसे शब्द शामिल थे.

भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेना के बीच

सामुद्रिक सुरक्षा बैठक

भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं तथा तटरक्षकों के प्रतिनिधियों के बीच वार्षिक आईएमबीएल बैठक का 33वां संस्करण शुक्रवार को आईएनएस सुमित्रा पर पाक खाड़ी में प्वाइंट कैलिमेरे के पास भारत-श्रीलंका समुद्री सीमा रेखा पर आयोजित किया गया था। दोनों देशों के समकक्षों के बीच परस्पर बातचीत दोनों देशों की नौसेनाओं और सीजी के लिए प्रचालनों में सहयोगों और तालमेल को और अधिक बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में काम करती है।

श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्रीलंका नौसेना के उत्तर मध्य नौसेना क्षेत्र (एनसीएनए) के कमांडर आरएडीएम बीएकेएस बानागोडा ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तमिलनाडु और पुडुचेरी नौसेना क्षेत्र (एफओटीएनए) के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग आरएडीएम रवि कुमार ढींगरा ने किया। तटरक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय (पूर्व) के प्रतिनिधि, कोलंबो में भारतीय उच्चायोग के रक्षा सलाहकार और दोनों देशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बातचीत में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान, दोनों नौसेनाओं और तटरक्षक बल के उपस्थित लोगों ने पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, मछुआरों की सुरक्षा, प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के उपायों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। विद्यमान संचार नेटवर्क को बढ़ाने और समय पर कार्रवाई में सहायता करने वाले दोनों नौसेनाओं और तटरक्षक बल के बीच सूचनाओं को समय पर साझा करने के तरीकों और साधनों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने प्रचालनों में परस्पर सहयोग के महत्व की पुष्टि की और क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को सुदृढ बनाने हेतु लिए गए निर्णयों को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

भारतीय नौसेना की परियोजना 15बी के युद्धपोत सूरत के शिखर का अनावरण समारोह

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने सूरत नगर में आयोजित एक जीवंत समारोह में भारतीय नौसेना के नवीनतम, निर्माणाधीन, निर्देशित मिसाइल विध्वंसक 'सूरत' के शिखर का अनावरण (क्रेस्ट अनवेलिंग) नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और राज्य सरकार एवं भारतीय नौसेना के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों तथा अधिकारियों की उपस्थिति में किया।

सूरत का शिखर खंभात की खाड़ी के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर स्थित हजीरा (सूरत) के प्रसिद्ध प्रकाश स्तंभ (लाइट हाउस) को दर्शाता है। 1836 में निर्मित यह लाइटहाउस भारत के सबसे पहले के लाइटहाउसों में से एक था। शिखर पर एशियाई शेर, जो कि गुजरात का राज्य पशु भी है, इस पोत की महिमा और शक्ति का प्रतीक है। नौसैनिक युद्ध प्रौद्योगिकी और लड़ाकू क्षमताओं में नवीनतम प्रगति से सुसज्जित, युद्धपोत सूरत समुद्री सुरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा के लिए नौसेना की प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली अवतार है। इसे शिखर पर चित्रित लहरदार समुद्र द्वारा अच्छी तरह से दर्शाया गया है। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने की दहलीज पर स्थित युद्धपोत सूरत एक दुर्जेय प्रहरी के रूप में काम करने, देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने और क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को बनाए रखने के लिए आश्वस्त करता है। स्वदेशी रूप से अभिकल्पित एवं निर्मित परियोजना 15बी [विशाखापत्तनम (श्रेणी)] विध्वंसक वर्ग का यह चौथा युद्धपोत सूरत नौसेना प्रौद्योगिकी और क्षमताओं में एक उल्लेखनीय छलांग का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस पोत का निर्माण नवीन ब्लॉक निर्माण पद्धति का उपयोग करके किया गया है, जिसमें मुंबई में मझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल) में एकीकृत किए जाने से पहले इस पोत के पतवार को अलग-अलग भौगोलिक स्थानों पर परिश्रमपूर्वक जोड़ा गया है। जटिल परिशुद्धता और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता को उजागर करते हुए, यह पद्धति भारत की पोत निर्माण क्षमता के बढ़ते कौशल को भी रेखांकित करती है।

अपने समृद्ध समुद्री इतिहास और पोत निर्माण की विरासत के लिए प्रसिद्ध एवं जीवंत नगर सूरत के नाम पर नामित, यह युद्धपोत सूरत भी अपने नाम की उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता की भावना का प्रतीक है।

प्रोजेक्ट 15बी, प्रोजेक्ट 15ए [कोलकाता श्रेणी] की सफलता का अनुसरण करने के साथ ही भारत की लगातार बढ़ती नौसैनिक शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। सूरत युद्धपोत का निर्माण स्वदेशी अत्याधुनिक समुद्री प्रौद्योगिकी के प्रति राष्ट्र के समर्पण और रणनीतिक सैन्य प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण है।

पाकिस्तान में बैठकर भारत में आतंक का खूनी खेल खेलने वाले आतंकियों का सफाया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में एनसीसी कैडेट को संबोधित करते हुए कहा था कि आज पूरा विश्व कह रहा है कि भारत न केवल संभावनाओं से भरा है, बल्कि भारत उन सभी को भी पूरा कर रहा है, चाहे वह आर्थिक स्थिति हो या हमारे दुश्मनों से लड़ने की हमारी क्षमता हो। हमारी सेना को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि हम छेड़ते नहीं हैं लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो हम छोड़ते नहीं हैं। हम हपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाने से नहीं चूकेंगे। आज यह देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारतीय सुरक्षाबल केवल सीमा पर ही तैनात नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने दुश्मन एक-एक कर विदेशी धरती पर मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में बैठकर भारत में आतंक का खूनी खेल खेलने वाले आतंकियों के सिर पर इन दिनों मानों काल मंडरा रहा है। आए दिन खूंखार आतंकियों के मारे जाने की खबर आ रही है। अब पंजाब के सियालकोट जिले के पसरूर तहसील के खोखरान चौक पर अज्ञात हमलावरों ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मोहम्मद मुजमिल और उसके सहयोगी नईमुर रहमान को मौत के घाट उतार दिया।

2022 से अब तक 23 आतंकवादी मारे गए, 2023 में 18 ढेर

पिछले कुछ महीनों में विदेशी धरती पर भारत विरोधी हरदीप सिंह निज्जर, अवतार सिंह खांडा, परमजीत पंजवार, रिपुदमन सिंह मलिक, हरविंदर रिंडा, सुखदूल सिंह, हैप्पी संघेड़ा के साथ ही अबू कासिम, जहूर मिस्त्री, अब्दुल सलाम भुट्टावी, सैयद नूर, एजाज अहमद, खालिद रजा, बशीर अहमद, शाहिद लतीफ, मुफ्ती कैसर फारूक, जियाउर रहमान, मलिक दाऊद, सुक्खा दुनिके, ख्वाजा शाहिद, मौलाना तारिक रहीम उल्लाह तारिक जैसे आतंकियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। वर्ष 2023 में अब तक 18 भारत विरोधी आतंकवादी विदेशों में मारे जा चुके हैं। वहीं 2022 में पांच भारत विरोधी आतंकवादी मारे गए थे।

ये नया भारत है, एक-एक कर मरते जा रहे आतंकवादी

पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरह भारत का कद बढ़ता जा रहा है, वह विदेशी ताकतों को पसंद नहीं आ रहा है। इसीलिए वे तरह-तरह के प्रपंच कर भारत को बदनाम करने, उसकी विकास की रफ्तार को रोकने के षडयंत्र में जुटे हैं। लेकिन यह नया भारत है, भारत के दुश्मन जहां कहीं भी हो उनका खत्म होना निश्चित है, चाहे वे कहीं भी छिपे हों। 2014 से पहले की सरकारें आतंकवादी हमला होने पर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका जैसे देशों से निहोरा करती थीं कि वे इसकी निंदा करें और भारत को इन आतंकवादी हमलों से बचाएं। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत इस कदर सशक्त, सबल और सक्षम हुआ है कि अब वह दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देता है। यही वजह है कि अब भारत नहीं, पाकिस्तान खुद को आतंकवाद से पीड़ित बता रहा है।

लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी मोहम्मद मुजमिल मारा गया

पाकिस्तान में बैठकर भारत में आतंक का खूनी खेल खेलने वाले आतंकियों के बुरे दिन आ गए हैं। पंजाब के सियालकोट जिले के पसरूर तहसील के खोखरान चौक पर अज्ञात हमलावरों ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मोहम्मद मुजमिल और उसके सहयोगी नईमुर रहमान को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि चौक पर एक सफेद रंग की कार खड़ी है। इसी दौरान एक बाइक पर सवार होकर दो लोग आते हैं। पीछे बैठा व्यक्ति राइफल लिए हुए था। बाइक से उतरते ही उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसने पहले दुकान में मौजूद लोगों पर फिर कार में सवार लोगों पर फायरिंग की। गोली चलने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इस दौरान हमलावर लगातार फायरिंग करता रहा। जब उसे लगा कि टारगेट मारा गया है तो वह बाइक पर सवार हुआ और भाग गया।

भारत विरोधी जैश सरगना मसूद अजहर का करीबी तारिक रहीम उल्लाह की हत्या

भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी मौलाना तारिक रहीम उल्लाह तारिक को पाकिस्तान में 12 नवंबर को ढेर कर दिया गया। जैश सरगना मसूद अजहर के करीबी मौलाना तारिक की हत्या उस समय हुई जब वह भारत विरोधी एक रैली में हिस्सा लेने के लिए जा रहा था। मौलाना जिस सभा में शामिल होने के लिए जा रहा था, वह कराची के ओरंगी टाउन में आयोजित हो रही थी। इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। मौलाना पर अचानक गोलियां चलीं और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तारिक पाकिस्तान का एक मशहूर मौलाना था जिसे सुनने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती थी। कराची पुलिस का कहना है कि मौलाना की हत्या टारगेट किलिंग से जुड़ी हो सकती है।

9 नवंबर 2023

भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले लश्कर आतंकी अकरम खान गाजी ढेर - भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला लश्कर आतंकी अकरम खान उर्फ अकरम गाजी की पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकी अकरम गाजी ने साल 2018 से 2020 तक लश्कर भर्ती सेल का नेतृत्व किया था। साथ ही वह पाकिस्तान में अपने भारत विरोधी भड़काऊ बयानों के लिए के लिए जाना जाता था। अकरम लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का पूर्व कमांडर था। वह लंबे समय से चरमपंथी गतिविधियों में शामिल था। साथ ही उसने लश्कर भर्ती सेल का नेतृत्व किया था। उसे 9 नवंबर 2023 की रात अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी।

यूपी में पांच एक्सप्रेसवे के किनारे बनेंगे 30 औद्योगिक गलियारे

एक्सप्रेसवे के जरिए प्रदेश की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ ही अब इनके किनारे औद्योगिक केंद्रों की स्थापना के लिए औद्योगिक गलियारे विकसित किए जाने की योजना पर अमल शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) ने औद्योगिक गलियारे के लिए 30 स्थानों का चयन कर लिया है। यूपीडा प्रदेश में पांच एक्सप्रेसवेज के किनारे औद्योगिक गलियारों की स्थापना करेगा। इनमें आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे एवं गंगा एक्सप्रेसवे शामिल हैं। 5800 हेक्टेयर पर विकसित होने वाले औद्योगिक गलियारों के निर्माण पर करीब सात हजार करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया गया है।

सीएम योगी को दिया गया विवरण

हाल ही में एक उच्चस्तरीय बैठक में सीएम योगी के समक्ष इन पांचों एक्सप्रेसवेज के किनारे चिह्नित औद्योगिक गलियारों का विवरण प्रस्तुत किया। इसके अनुसार प्रदेश के 12 जिलों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर 11 स्थलों को औद्योगिक गलियारे के लिए चुना गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1522 हेक्टेयर है। इस पर करीब 2300 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है।

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे: 1500 करोड़ रुपये का व्यय

इसी तरह, सात जिलों को जोड़ने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे छह स्थलों को चिह्नित किया गया है। इसका प्रस्तावित क्षेत्रफल 1884 हेक्टेयर है और इस पर 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा व्यय का अनुमान है।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे: 650 करोड़ का व्यय

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़े 10 जिलों में पांच स्थानों का चयन किया गया है। इसका कुल क्षेत्रफल 532 हेक्टेयर है और इनके विकास पर करीब 650 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे: 2300 करोड़ व्यय का संभव

नौ जिलों को जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक गलियारे के लिए पांच स्थानों का चयन किया गया है, जिसका प्रस्तावित क्षेत्रफल 1586 हेक्टेयर और अनुमानित व्यय 2300 करोड़ होने की संभावना है।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे: 320 करोड़ व्यय - पांचवां और अंतिम एक्सप्रेसवे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है। इसके चार जिलों के दो स्थानों को औद्योगिक केंद्रों के लिए चुना गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 345 हेक्टेयर होगा और अनुमानित व्यय 320 करोड़ होने की संभावना है।

108 गांवों को किया गया अधिसूचित - यूपीडा की ओर से चिह्नित सभी 30 स्थलों से जुड़े 108 गांवों को प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचित किया जा चुका है। वहीं, भूमि क्रय के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को 200 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। साथ ही भूमि क्रय के लिए बुंदेलखंड औद्योगिक प्राधिकरण की तर्ज पर 1500 करोड़ रुपये अवमुक्त किए जाने का आदेश भी निर्गत किया जा चुका है। जिला स्तर पर भूमि क्रय के लिए दरों का निर्धारण फिलहाल प्रक्रिया में है।

भारत पोस्ट-प्रोडक्शन उद्योग का केंद्र बन रहा

- **केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 54वें इफ्फी के अंतर्गत वीएफएक्स और टेक पवेलियन का उद्घाटन किया**
- **नए तकनीकी हस्तक्षेपों को अपनाते हुए भारत पोस्ट-प्रोडक्शन उद्योग का केंद्र बन रहा है: सूचना एवं प्रसारण मंत्री**

''वीएफएक्स और टेक पवेलियन भारत में पोस्ट प्रोडक्शन उद्योग को और अधिक बढ़ावा देंगे"

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) के अंतर्गत वीएफएक्स और टेक पवेलियन का उद्घाटन किया। इफ्फी में एनएफडीसी द्वारा फिल्म बाजार के इतिहास में पहली बार स्थापित, वीएफएक्स और टेक पवेलियन एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, वर्चुअल रियलिटी और सीजीआई के क्षेत्र में फिल्म निर्माण तकनीक में कुछ सबसे गतिशील, गहन और अत्याधुनिक प्रगति का प्रदर्शन करेगा।

श्री ठाकुर ने सिने संग्रहालय, अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स के व्यूइंग ज़ोन आदि सहित पवेलियन के विभिन्न खंडों का उद्घाटन और निरीक्षण किया। श्री ठाकुर ने सोनी के फुल फ्रेम सिनेमा लाइन कैमरों के उपयोग को देखा-समझा और 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमॉरो पहल के तहत चुने गए युवा फिल्म निर्माताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने टेक पवेलियन के बुक टू बॉक्स खंड के तहत चयनित लेखकों के साथ भी बातचीत की।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री फुल फ्रेम सिने कैमरे के उपयोग को देखते-समझते हुए

श्री ठाकुर ने कहा कि 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी मीडिया और मनोरंजन अर्थव्यवस्था बनने तक की भारत की प्रगति अभूतपूर्व रही है। उन्होंने कहा, ''देश में निर्मित फिल्म और मीडिया सामग्री की प्रतिभा और मात्रा को देखते हुए, भारत जल्द ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मीडिया और मनोरंजन उद्योग बन जाएगा।"

श्री ठाकुर ने कहा कि भारत फिल्म निर्माण के नए तकनीकी हस्तक्षेप और नवाचारों को अपना रहा है। उन्होंने कहा, ''हमारे युवाओं और बच्चों की प्रतिभा और हमारे उद्योग जगत के अग्रणी लोगों के नवाचार द्वारा समर्थित फिल्म शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन की बदौलत भारत सबसे अधिक मांग वाला गंतव्य है।"

नए तकनीकी हस्तक्षेपों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए श्री ठाकुर ने कहा, "भारत कहानी सुनाने वालों का देश है और लोग गहन, रचनात्मक और मौलिक सामग्री पसंद करते हैं और उसका लुत्फ उठाते हैं।" श्री ठाकुर ने कहा कि सामग्री का सृजन करने वालों को मनोरंजन के साथ-साथ दर्शकों को सूचित करने और शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए मीडिया और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में निरंतर विकसित हो रही प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए।

श्री ठाकुर ने कहा, ''भारत पोस्ट-प्रोडक्शन का केंद्र है। उन्होंने कहा कि नव स्थापित वीएफएक्स और टेक पवेलियन फिल्म निर्माण के क्षेत्र में पोस्ट-प्रोडक्शन को और अधिक बढ़ावा देंगे।"

रचनात्मक और एआई क्षेत्रों के विशेषज्ञ आभासी दुनिया तैयार करके, बुद्धिमान पात्रों का सृजन करके और दृश्यों की हद से पार जाने के लिए व्यक्तिगत अनुभव साझा करके फिल्म निर्माण में संभावनाओं और प्रगति की संभावनाओं का द्वार खोलेंगे।

इस वर्ष के भाग लेने वाले कुछ सम्मानित ब्रांडों में गूगल आर्ट्स एंड कल्चर, नेटफ्लिक्स, और अमेजॉन शामिल हैं। इस अवसर श्री ठाकुर के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव सुश्री नीरजा शेखर; और श्री पृथुल कुमार, संयुक्त सचिव (फिल्म), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और एमडी, एनएफडीसी भी मौजूद थे।

वर्ल्ड फूड इंडिया 2023

भारत की जीवंत विरासत

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित 'वर्ल्ड फूड इंडिया 2023' कार्यक्रम 5 नवंबर को भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। समापन सत्र में इस कार्यक्रम की शानदार सफलता का उल्लेख किया गया, जिसमें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने भारत की जीवंत पाक विरासत को प्रदर्शित करने और विभिन्न उद्योगों के बीच एक मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। उन्होंने वैश्विक पाक केंद्र के रूप में देश की क्षमता पर जोर देते हुए वैश्विक भूख से निपटने के लिए खाद्य वितरण को बढ़ाने के महत्व का उल्लेख किया।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन 3 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों के लिए मूल पूंजी सहायता का वितरण करके किया था। उन्होंने भारत को 'दुनिया की खाद्य टोकरी' के रूप में प्रस्तुत करने और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने में इस कार्यक्रम की भूमिका पर जोर दिया। प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप पैवेलियन तथा फूड स्ट्रीट की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने भविष्य की अर्थव्यवस्था को साकार करने में इसकी भूमिका पर जोर दिया। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को 'सनराइज़ सैक्टर' के रूप के रूप में मान्यता देते हुए, उन्होंने नौ वर्षों में पचास हजार करोड़ रुपये से अधिक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आकर्षण पर में प्रकाश डाला। उन्होंने मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे में हजारों करोड़ के निवेश पर जोर देते हुए पीएलआई योजना और एग्री-इंफ्रा फंड के तहत चल रही परियोजनाओं के प्रभाव को रेखांकित किया।

भारत सरकार के दस मंत्रालयों/विभागों, छह कमोडिटी बोर्डों और 25 राज्यों के सहयोग से आयोजित मेगा फूड इवेंट ने महत्वपूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हितधारकों का ध्यान आकर्षित किया। इस आयोजन में 1208 प्रदर्शकों, 14 देश के मंडपों और 715 अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों, 218 घरेलू खरीदारों और 97 कॉर्पोरेट दिग्गजों की उल्लेखनीय भागीदारी रही। सात प्रदर्शनी हॉलों में पचास हजार वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में फैले इस कार्यक्रम ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में हुई नवीनतम प्रगति का प्रदर्शन करने के लिए एक व्यापक मंच उपलब्ध कराया। इस कार्यक्रम में सात मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों सहित 14 देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। इस आयोजन की वैश्विक अपील को भागीदार देश के रूप में नीदरलैंड और फोकस देश के रूप में जापान की विशिष्ट भागीदारी से और अधिक मजबूती मिली।

विश्व खाद्य भारत 2023 के उद्घाटन दिवस के अवसर पर एक प्रतिष्ठित सीईओ गोलमेज सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस तथा वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल की सह-अध्यक्षता में हुआ। इस महत्वपूर्ण सभा में खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध क्षेत्रों की 70 से अधिक अग्रणी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सीईओ एक मंच पर शामिल हुए। इस गोलमेज सम्मेलन के दौरान हुए मुख्य विचार-विमर्श में व्यवसाय संचालन, निवेश रणनीतियों, सोर्सिंग हितों और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में मौजूदा अंतरालों की व्यापक जांच करना शामिल रहा।

इस आयोजन के दौरान श्री पशुपति कुमार पारस ने छह जी2जी बैठकों में भाग लिया। उन्होंने फिजी और मॉरीशस के मंत्रियों के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वैश्विक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में चर्चा की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में इस कार्यक्रम की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए ग्रीस और लेबनान के गणमान्य व्यक्तियों के साथ भी बातचीत की। मॉरीशस के कृषि-उद्योग और खाद्य सुरक्षा मंत्री और ऑस्ट्रेलिया के सांसद के साथ अयोजित चर्चा में ज्ञान साझा करने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जोर दिया गया।

तीन दिवसीय कार्यक्रम में 48 सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें विषयगत, राज्य, संबद्ध मंत्रालय और देश और संगठन सत्र शामिल रहे। विशेष रूप से, 16 विषयगत सत्रों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वित्तीय सशक्तिकरण, गुणवत्ता आश्वासन, मशीनरी और प्रौद्योगिकी में नवाचार, ई-कॉमर्स तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इसके अलावा, डीपीआईआईटी और एफएसएसएआई सहित संबद्ध मंत्रालयों द्वारा 12 राज्य-केंद्रित पैनल चर्चाओं और 11 विशेष सत्रों में प्रासंगिक उद्योग चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई। इन सत्रों में गुजरात, केरल और आंध्र प्रदेश के मंत्रियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

इस कार्यक्रम में ज्ञान के आदान-प्रदान और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीदरलैंड और जापान द्वारा ज्ञान सत्रों की भी मेजबानी कराई गई। इसके अलावा नीदरलैंड, यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम, ब्राजील और संयुक्त अरब अमीरात के साथ आयोजित सफल बैठकों में भारत के

एक समृद्ध एवं सुरक्षित की दिशा में
हिंद-प्रशांत क्षेत्र

भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष-स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन - हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद (आईपीआरडी) - 15 से 17 नवंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 15 नवंबर 23 को माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का मुख्य भाषण और विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों व भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के विशेष संबोधनों की एक श्रृंखला शामिल होगी, जो इस मेगा सम्मेलन में होने वाले विचार-विमर्शों को व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु डिजाइन की गई है। आईपीआरडी, गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2023 के अनुसरण में है। यह कॉन्क्लेव भारतीय नौसेना द्वारा 29 से 31 अक्टूबर 2023 के दौरान गोवा में आयोजित किया गया था। वैचारिक दृष्टि से, गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना प्रमुखों और समुद्री एजेंसियों के प्रमुखों को एक मंच प्रदान करके रणनीतिक-परिचालन स्तर पर भारतीय नौसेना की सहकारी भागीदारी को पेश करना था। दूसरी ओर, आईपीआरडी रणनीतिक स्तर पर नौसेना की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी की प्रमुख अभिव्यक्ति है, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में 'समग्र' समुद्री सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करती है।

आईपीआरडी के पहले दो संस्करण क्रमशः 2018 और 2019 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। आईपीआरडी 2020 को कोविड-19 के प्रकोप के कारण रद्द कर दिया गया था। आईपीआरडी का तीसरा संस्करण 2021 में ऑनलाइन मोड में आयोजित किया गया था और चौथा संस्करण 2022 में नई दिल्ली में भौतिक प्रारूप में आयोजित किया गया था। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन (एनएमएफ) भारतीय नौसेना का ज्ञान संबंधी भागीदार और आईपीआरडी के प्रत्येक संस्करण का मुख्य आयोजक है, जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र के भीतर विभिन्न समुद्री रुझानों, क्षेत्रीय अवसरों और वहां उत्पन्न होने वाली चुनौतियों की समीक्षा करना और प्रमुख हितधारकों के बीच समाधान-उन्मुख संवाद के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।

आईपीआरडी 2023 का विषय

आईपीआरडी-2023 का व्यापक विषय "हिंद-प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू-राजनैतिक प्रभाव" है। आईपीआरडी का इस वर्ष का संस्करण पिछले संस्करण पर आधारित है, जो विशेष रूप से "हिंद-प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई) के 'व्यापार, कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन' स्तंभ पर ध्यान केन्द्रित करके आईपीओआई को संचालित करने" पर केन्द्रित था। निस्संदेह, 'व्यापार' और 'समुद्री परिवहन' दोनों समुद्री कनेक्टिविटी के खंड हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 09 अगस्त 2021 को "समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना: अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक मामला" विषय पर यूएनएससी में आयोजित उच्च-स्तरीय खुली बहस में अपने संबोधन में "जिम्मेदार समुद्री कनेक्टिविटी" के सिद्धांत का समर्थन किया था। उस संबोधन में उन्होंने विशेष रूप से समुद्री बुनियादी ढांचे के निर्माण के तीन प्रमुख पहलुओं यानीऐसी परियोजनाओं की भौतिक स्थिरता, उन देशों की अवशोषण क्षमता जहां इस तरह के बुनियादी ढांचे को विकसित करने का प्रस्ताव है, और समुद्री बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए उपयुक्त वैश्विक मानदंडों एवं मानकों पर जोर दिया था। हालांकि भू-राजनैतिक व्यवधान, चाहे वे कहीं भी हों, महत्वपूर्ण समुद्री चुनौतियां पैदा करते हैं, जिनमें व्यापार और समुद्री कनेक्टिविटी पर प्रतिकूल प्रभाव भी शामिल है। ये चुनौतियां हाल के वर्षों में घटित घटनाओं - कोविड-19 महामारी से लेकर बढ़ते तनाव की सामुद्रिक अभिव्यक्तियों के साथ-साथ भू-राजनैतिक होड़ में तेजी से उलझती दुनिया में फैलते सशस्त्र संघर्षों - में स्पष्ट रही हैं।

इसलिए, आईपीआरडी-2023, विश्व स्तर पर प्रसिद्ध विषय-वस्तु विशेषज्ञों और प्रख्यात वक्ताओं की एक श्रृंखला की एजेंसी के माध्यम से, तीन-दिवसीय अवधि में विस्तृत छह पेशेवर सत्रों के माध्यम से हिंद-प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू-राजनैतिक प्रभावों का पता लगाएगा

9 वर्षों में भारत की जैव-अर्थव्यवस्था में वर्ष-दर-वर्ष दहाई अंक की वृद्धि

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत वर्ष 2025 तक शीर्ष 5 वैश्विक जैव-विनिर्माण हब में शामिल होने के लिए तैयार है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा, जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक व्यापार और भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली जैव-अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण साधन बनने की क्षमता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री ने जैव प्रौद्योगिकी पर एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन "ग्लोबल बायो-इंडिया- 2023" की वेबसाइट लॉन्च करते हुए कहा, यह सम्मेलन 4 से 6 दिसंबर, 2023 तक प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी बायोइकोनॉमी ने पिछले 9 वर्षों में वर्ष-दर-वर्ष दहाई अंक की विकास दर देखी है। उन्होंने कहा कि भारत को अब दुनिया के शीर्ष 12 जैव प्रौद्योगिकी गंतव्य स्थलों में मूल्यांकित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "वर्ष 2014 में, भारत की जैव-अर्थव्यवस्था लगभग 10 बिलियन डॉलर थी, आज यह 80 बिलियन डॉलर है। केवल 8/9 वर्षों में यह 8 गुना बढ़ गया है और हम वर्ष 2030 तक इसके 300 अरब डॉलर होने की आशा करते हैं"।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाले समय में बायोइकोनॉमी आजीविका का एक वृहद लाभकारी स्रोत बनने जा रही है। उन्होंने कहा, "भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र पिछले तीन दशकों में विकसित हुआ है और इसने स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, उद्योग और जैव-सूचना विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है"। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि बायोटेक स्टार्टअप भारत की भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, "बायोटेक स्टार्टअप पिछले 8 वर्षों में 100 गुना बढ़ गए हैं, जो 2014 में 52 स्टार्टअप से बढ़कर वर्तमान में 6,300 से अधिक हो गए हैं। व्यवहारिक तकनीकी समाधान प्रदान करने की आकांक्षाओं के साथ भारत में प्रति दिन 3 बायोटेक स्टार्ट-अप शामिल हो रहे हैं"। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी भविष्य की तकनीक है क्योंकि आईटी पहले ही अपने संतृप्ति स्तर पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा, "भारत के पास जैव संसाधनों की एक विशाल संपदा है, एक असंतृप्त संसाधन जिसका उपयोग किया जाना बाकी है और विशेष रूप से विशाल जैव विविधता एवं हिमालय में अद्वितीय जैव संसाधनों के कारण जैव प्रौद्योगिकी में एक लाभ है। फिर 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है और पिछले साल हमने समुद्रयान लॉन्च किया था जो समुद्र के नीचे जैव विविधता की खोज करने वाला है"। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप जीव विज्ञान और विनिर्माण के नए शोध को मिलाकर एक अलग शैली है, जैसे कि जीवित प्रणालियों का प्रसंस्करण जिसमें सूक्ष्म जीव, स्व-संस्कृतियां आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा, "जैव प्रौद्योगिकी आपको एक परिवेश, एक ऐसा वातावरण प्रदान करती है जो स्वच्छ, हरा-भरा और आपके जीवन के लिए अधिक अनुकूल होगा, फिर आपकी हिस्सेदारी इससे जुड़ जाती है। और जैसे-जैसे समय बीतता है, यह आजीविका के आकर्षक स्रोत भी पैदा करता है, साथ ही पेट्रोकेमिकल-आधारित विनिर्माण जैसे जैव-आधारित उत्पाद जैसे खाद्य योजक, बायोइंजीनियरिंग संबंध, पशु चारा उत्पाद के विकल्प भी पैदा करता है"।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज 3,000 से अधिक एग्रीटेक स्टार्टअप हैं और अरोमा मिशन और लैवेंडर की खेती जैसे क्षेत्रों में बहुत सफल हैं।

उन्होंने कहा, "लगभग 4,000 लोग लैवेंडर की खेती कर रहे हैं और लाखों रुपये कमा रहे हैं, उनमें से कुछ के पास उच्च शैक्षिक योग्यता नहीं है, लेकिन वे बहुत नवोन्मेषक हैं।" डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग उन्नत जैव ईंधन और 'अपशिष्ट से ऊर्जा' प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास नवाचारों का समर्थन कर रहा है।

रामलला का भव्य मंदिर तेजी से हो रहा तैयार

अयोध्या: अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य बेहद ही तेजी से चल रहा है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसी मंदिर में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा होने वाले है। प्रतिष्ठापन समारोह के लिए वैदिक अनुष्ठान मुख्य समारोह से एक सप्ताह पहले अगले साल 16 जनवरी से शुरू होंगे। वाराणसी के वैदिक पुजारी लक्ष्मी कांत दीक्षित, 22 जनवरी, 2024 को राम लला के अभिषेक समारोह का मुख्य अनुष्ठान करेंगे। उससे पहले राम मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य संपन्न हो जाएगा।

इस निर्माण कार्य की ड्रोन आई व्यू तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर साझा की हैं। इन तस्वीरों से आप मंदिर की भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि मंदिर का निर्माण कार्य अपने अंतिम दौर में है। ज्योतिषियों और वैदिक पुजारियों से परामर्श के बाद, श्री राम जन्मभूमि तीरथ क्षेत्र ट्रस्ट ने 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे से 12.45 बजे के बीच राम मंदिर के गर्भगृह में राम लला को विराजमान करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण-प्रतिष्ठा (अभिषेक) समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया, "राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रोटोकॉल के तहत (प्रधानमंत्री की उपस्थिति में) समारोह में शामिल होंगे।" उन्होंने कहा कि आमंत्रित अतिथि प्रधानमंत्री के जाने के बाद ही राम लला के दर्शन कर सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, "ट्रस्ट ने राम लला के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के लिए सभी संप्रदायों के 4,000 संतों को आमंत्रित किया है।"

विजय दिवस

हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जो 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की याद दिलाता है। यह भारत के सैन्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था और देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़ने वाले सैनिकों की बहादुरी और वीरता का प्रमाण था।

कारगिल युद्ध एक सशस्त्र संघर्ष था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल, लद्दाख की ऊंचाई वाली पहाड़ियों में हुआ था। एक गुप्त ऑपरेशन में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने नियंत्रण रेखा (LOC) के पार रणनीतिक जगहों पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना ने घुसपैठियों को बेदखल करने और कब्जे वाले क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए एक बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया।

यह युद्ध अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों, कठिन भूभाग, कठोर मौसम और सीमित संसाधनों के बीच लड़ा गया था। हालांकि, सैनिकों ने प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में अद्वितीय साहस, दृढ़ संकल्प और लचीलापन दिखाया।

वे करीबी लड़ाई में लगे रहे, खतरनाक चोटियों पर चढ़े और दुश्मन की भारी गोलाबारी का सामना किया। भारतीय वायु सेना ने दुश्मन को खदेड़ने के लिए हवाई हमले करते हुए महत्वपूर्ण हवाई सहायता प्रदान की।

कारगिल युद्ध ने भारतीय सशस्त्र बलों और पूरे देश की अदम्य भावना और एकता का प्रदर्शन किया। सैनिकों द्वारा दिए गए बलिदान बहुत बड़े थे, जिनमें से कई ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

उनकी वीरता और उद्देश्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने पूरे देश को प्रेरित किया और दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया।

कारगिल विजय दिवस हमारे सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की याद दिलाता है। यह उन नायकों को श्रद्धांजलि देने का दिन है, जिन्होंने देश के लिए निस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़ी।

यह दिन विभिन्न समारोहों, स्मारक सेवाओं, पुष्पांजलि समारोहों और "विजय ज्वाला" को जलाने का प्रतीक है। यह शहीद सैनिकों को सम्मान देने, दिग्गजों के प्रति आभार व्यक्त करने और शहीदों के परिवारों को समर्थन देने का अवसर है।

देवियो और सज्जनों,

आज, हम अपने देश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए यहां हैं। इस दिन हम उन बहादुर सैनिकों को याद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान हमारे प्यारे देश की संप्रभुता की रक्षा करते हुए बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी।

कारगिल युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं था, यह हमारे देश की ताकत, एकता और लचीलेपन की परीक्षा थी। हमारे सैनिकों को कठिन इलाकों, खराब मौसम और दृढ़ दुश्मन से जूझते हुए अत्यधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

कारगिल की बर्फीली चोटियों से घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए लड़ते समय उन्होंने अटूट साहस और अदम्य भावना का परिचय दिया।

उनके बलिदान बहुत बड़े थे। उन्होंने हमारी सीमाओं की रक्षा और हमारी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी वीरता और निस्वार्थता के कार्य हम सभी के लिए प्रेरणा का काम करते हैं।

उन्होंने देशभक्ति का सही अर्थ प्रदर्शित किया और हमें अपने राष्ट्र की रक्षा का महत्व दिखाया।कारगिल विजय दिवस इन वीर जवानों को याद करने और सम्मान देने का दिन है। यह उनकी सेवा और बलिदान के प्रति हमारी कृतज्ञता और प्रशंसा व्यक्त करने का दिन है। यह शहीदों के परिवारों को समर्थन देने और राष्ट्र के प्रति उनके अपार योगदान को स्वीकार करने का भी दिन है।

जैसा कि हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं, आइए हम अपने सैनिकों द्वारा दिए गए बलिदान को कभी नहीं भूलने की प्रतिज्ञा करें।

आइए हम उनकी विरासत को बनाए रखने का प्रयास करें और एक मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र के निर्माण की दिशा में काम करें।

उनकी वीरता हमें जीवन के सभी क्षेत्रों से प्रेरित करती रहे।

2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। मोदी राज में भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही दुनिया के विकास का इंजन बनकर उभरेगा। मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस बात पर ब्रोकरेज कंपनी मॉर्गन स्टेनली ने भी मुहर लगा दी है। मॉर्गन स्टेनली की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत साल 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी डॉलर के आधार पर भारत की सांकेतिक जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2025 तक बढ़कर 12.4 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी और यह चीन, अमेरिका और यूरो क्षेत्र से बेहतर प्रदर्शन करेगी। यह वित्त वर्ष 2024 में सात प्रतिशत रहेगी। उच्च विकास दर के कारण भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से बढ़ेगी। मॉर्गन स्टेनली ने कहा है कि उम्मीद है कि 2027 तक सांकेतिक जीडीपी पांच लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी, जिससे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

साल 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत- जेपी मॉर्गन

जेपी मॉर्गन ने भी कहा है कि अब भारत के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में ज्यादा देर नहीं है। जेपी मॉर्गन के एशिया प्रशांत इक्विटी रिसर्च के मैनेजिंग डायरेक्टर जेम्स सुलिवन की मानें तो भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि 2030 तक भारत की जीडीपी दोगुनी से ज्यादा 7 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। बिजनेस न्यूज चैनल CNBC-TV18 के साथ एक इंटरव्यू में सुलिवन ने कहा कि अगले कुछ सालों में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी और इसका शेयर बाजार अच्छा प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि लंबी अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े संरचनात्मक बदलाव होंगे। सुलिवन ने कहा कि अगले कुछ महीनों में निर्यात में भी तेजी आने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि अभी जो 500 अरब डॉलर से कम का निर्यात है वो बढ़कर एक लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाने का अनुमान है।

2027-28 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा-आईएमएफ

यही भरोसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को भी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो अनुमान व्यक्त किया, उसके मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था, जो अभी लगभग 3.75 ट्रिलियन डॉलर की है, वित्त वर्ष 2027-28 तक 5 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगी। भारत 5.2 ट्रिलियन डॉलर के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो अनुमान व्यक्त किया, उसके मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था, जो अभी लगभग 3.75 ट्रिलियन डॉलर की है, वित्त वर्ष 2027-28 तक 5 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगी। भारत 5.2 ट्रिलियन डॉलर के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसकी वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। इस दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था 31 ट्रिलियन डॉलर के साथ शीर्ष पर रहेगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी 24 प्रतिशत होगी। इसके बाद चीन 25.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर रहेगा और वैश्विक जीडीपी में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

आइए देखते हैं देश की अर्थव्यवस्था और विकास पर विभिन्न संस्थानों और रेटिंग एजेंसियों का क्या कहना है...

ग्लोबल ग्रोथ में भारत की होगी 18 प्रतिशत हिस्सेदारी- आईएमएफ

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का मानना है कि भारत विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में भारत का योगदान अगले पांच साल में मौजूदा 16 प्रतिशत बढ़कर 18 प्रतिशत हो जाएगा। आईएमएफ के एशिया-प्रशांत विभाग के निदेशक कृष्णा श्रीनिवासन के अनुसार 2028 तक दुनिया की विकास दर में भारत की हिस्सेदारी 18 प्रतिशत होगी। आईएमएफ का मानना है कि बड़े पैमाने पर पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेजिलिएंट डोमेस्टिक डिमांड के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी हुई है। आईएमएफ डेटा के अनुसार वर्ष 2023 और 2024 में भारत और चीन ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में संयुक्त रूप से करीब आधा का योगदान करेंगे।

आईएमएफ ने ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 6.3 प्रतिशत किया

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया है। आईएमएफ ने अपनी ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि इस वित्त वर्ष में विकास दर 6.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही आईएमएफ ने कहा है कि 2024-25 में भी जीडीपी वृद्धि 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जबकि आइएमएफ ने वैश्विक विकास अनुमान को घटा दिया है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक वृद्धि 2023 में 3 प्रतिशत और 2024 में 2.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

चुनौतियों के बाद भी सबसे तेज रहेगी भारत की आर्थिक वृद्धि

दुनिया भर के तमाम अंतरराष्ट्रीय संगठनों का कहना है कि भारत आने वाले समय में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आईएमएफ के अनुमान के अनुसार रूस-यूक्रेन संकट, कोरोना महामारी और महंगाई जैसी चुनौतियों के बाद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगी। आईएमएफ ने कहा है कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में भारत की हिस्सेदारी 2028 तक फ्रांस और ब्रिटेन को पार कर जाने की उम्मीद है। इससे भारत वैश्विक आर्थिक विकास को चलाने में एक प्रमुख देश बन जाएगा। वैश्विक विकास में 75 प्रतिशत योगदान देने वाले 20 देशों में अमेरिका और चीन के साथ भारत शीर्ष योगदानकर्ताओं में बना हुआ है। 2023 में वैश्विक विकास में भारत का योगदान 15 प्रतिशत रहने की भी उम्मीद जताई गई है।

कई वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर है भारत

इसके पहले इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (IMF) की उपप्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की कई दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा कि भारत को लेकर दुनियाभर में पॉजिटिव सेंटीमेंट है। बहुत सारे बिजनेस और कंपनियां भारत को एक निवेश डेस्टिनेशन के रूप में देख रही हैं, क्योंकि वे चीन सहित दूसरे देशों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं।

आईएमएफ को भरोसा, वैश्विक अर्थव्यवस्था की अगुवाई करेगा भारत

इसके पहले आईएमएफ ने कहा था कि भारत की अगुवाई में दक्षिण एशिया वैश्विक वृद्धि का केंद्र बनने की दिशा में बढ़ रहा है और 2040 तक वृद्धि में इसका अकेले एक-तिहाई योगदान हो सकता है। आईएमएफ के हालिया शोध दस्तावेज में कहा गया कि बुनियादी ढांचे में सुधार और युवा कार्यबल का सफलतापूर्वक लाभ उठाकर यह 2040 तक वैश्विक वृद्धि में एक तिहाई योगदान दे सकता है। आईएमएफ की एशिया एवं प्रशांत विभाग की उप निदेशक एनी मेरी गुलडे वोल्फ ने कहा कि हम दक्षिण एशिया को वैश्विक वृद्धि केंद्र के रूप में आगे बढ़ता हुए देख रहे हैं।

मौजूदा वित्त वर्ष में 6.3 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी इंडियन इकोनॉमी- फिक्की

अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर यह है कि मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। उद्योग निकाय फिक्की के एक सर्वेक्षण में सोमवार को यह अनुमान लगाया गया है।

आर्थिक परिदृश्य पर फिक्की के सर्वे में कहा गया है कि 2023-24 के लिए वार्षिक औसत सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत रहेगी। इसमें न्यूनतम छह प्रतिशत और अधिकतम 6.6 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। सर्वे में इंडस्ट्री, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्रियों को शामिल किया गया। इस सर्वे को सितंबर के महीने में किया गया था।

वित्त वर्ष 2023-24 में 6.5 प्रतिशत रहेगी जीडीपी ग्रोथ रेट- आरबीआई - देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 में 6.5 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ेगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने मौजूदा वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान बरकरार रखा है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की द्विमासिक बैठक के बाद आरबीआईशक्तिकांत दास ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में जीडीपी विकास दर 6.0 प्रतिशत रह सकती है।

औद्योगिक प्रदूषण आपदा

2-3 दिसंबर की रात भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में हर साल 2 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। रिपोर्टर्स के मुताबिक उस गैस त्रासदी में जहरीली गैस के रिसाव के कारण पांच लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इतने सालों बाद आज भी पूरी दुनिया में इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक प्रदूषण आपदा के रूप में जाना जाता है। 1984 की उस गैस त्रासदी के दौरान प्राण गंवाने वाले लोगों की याद करने और प्रदूषण नियंत्रण कृत्यों के महत्व से हर व्यक्ति को अवगत कराने के लिए 2 दिसंबर का दिन राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में चिन्हित किया गया।

2-3 दिसंबर की रात भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में हर साल 2 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। रिपोर्टर्स के मुताबिक उस गैस त्रासदी में जहरीली गैस के रिसाव के कारण पांच लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इतने सालों बाद आज भी पूरी दुनिया में इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक प्रदूषण आपदा के रूप में जाना जाता है। 1984 की उस गैस त्रासदी के दौरान प्राण गंवाने वाले लोगों की याद करने और प्रदूषण नियंत्रण कृत्यों के महत्व से हर व्यक्ति को अवगत कराने के लिए 2 दिसंबर का दिन राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में चिन्हित किया गया। इस दिन का उद्देश्य प्रदूषण को रोकने में मदद करने वाले कानूनों के बारे में लोगों को जागरुक करना, औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन तथा नियंत्रण के प्रति जागरूकता फैलाना और औद्योगिक प्रक्रियाओं व मानवीय लापरवाही से पैदा प्रदूषण को रोकना है। देश के कई हिस्सों में पर्यावरण प्रदूषण को लेकर जो विकराल स्थिति बरकरार है, ऐसे में इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है।

प्रदूषण का सेहत पर असर

प्रदूषण आज न केवल भारत, बल्कि पूरी दनिया के लिए नासूर बनता जा रहा है, जिसकी वजह से बढ़ती बीमारियों के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ कई गुना बढ़ता जा रहा है। हवा में मौजूद प्रदूषण के कण न केवल दिल, दिमाग और फेफड़ों पर गंभीर असर डालते हैं बल्कि कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों का भी कारण बन रहे हैं। विशेषज्ञों का मत है कि प्रदूषण से उम्र पर पड़ने वाला प्रभाव धूम्रपान और टीबी जैसी बीमारियों से भी ज्यादा है और अगर प्रदूषण को लेकर WHO के मानकों का सख्ती से पालन किया जाए तो लोगों की उम्र में कई साल की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदूषण किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसी समस्या है, जिससे स्वयं को बचाने के लिए निजी स्तर पर कुछ विशेष नहीं कर सकते, बल्कि यह सामूहिक प्रयास है।

इस कार्यक्रम के लॉन्च के बाद से, नेटवर्क योजना निर्माण समूह की 54 बैठकों के दौरान 71.26 बिलियन डॉलर की 100 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। नेटवर्क योजना निर्माण समूह अवसंरचना योजना में गतिशक्ति सिद्धांतों को अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित एक महत्वपूर्ण संस्थागत निकाय है।

वैश्विक भूख के लिए पीएम मोदी का विजन:

'बाजरा में प्रचुरता' ग्रैमी बज़

एक अप्रत्याशित मोड़ में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की विशेषता वाले गीत "एबंडेंस इन मिलेट्स" ने 2024 ग्रैमी अवार्ड्स में नामांकन अर्जित किया है। यह मंजूरी सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणी में मिलती है, जो फालू और गौरव शाह द्वारा बनाए गए इस अद्वितीय संगीत प्रयास की वैश्विक मान्यता को प्रदर्शित करती है। उसी श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने वाली उल्लेखनीय प्रविष्टियाँ हैं जैसे अरूज़ आफताब, विजय अय्यर और शहजाद इस्माइली की "शैडो फोर्सेस", बर्ना बॉय की "अलोन", डेविडो की "फील", सिल्वाना एस्ट्राडा की "मिलाग्रो वाई डिसास्ट्रे" और बेला फ्लेक, एडगर मेयर और ज़ाकिर हुसैन "पश्तो" के साथ राकेश चौरसिया को पेश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, इब्राहिम मालौफ, सीमाफंक एंड टैंक और बंगास के साथ, "टोडो कोलोरेस" की दौड़ में हैं।

भारत में बाजरा का उत्थान और पतन - "बाजरा में प्रचुरता" की उत्पत्ति 'अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष' के जश्न में निहित है। यह गीत बाजरा के महत्व पर प्रकाश डालता है, जो एक छोटे दाने वाला, गर्म मौसम का अनाज है जो एक समय भारत के आहार का अभिन्न अंग था। पिछले कुछ वर्षों में, हरित क्रांति द्वारा गेहूं और चावल की अधिक पैदावार पर जोर देने के बाद, बाजरा पीछे की ओर चला गया और अस्पष्टता में चला गया। गीत का उद्देश्य स्पष्ट है: वैश्विक भूख के संभावित समाधान के रूप में बाजरा के बारे में जागरूकता को पुनर्जीवित करना।

फालू की वेबसाइट गीत की उत्पत्ति को रेखांकित करती है, यह देखते हुए कि भारत सरकार ने भारत को बाजरा के प्राथमिक उत्पादक के रूप में मान्यता देते हुए इस परियोजना का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को 72 देशों और संयुक्त राष्ट्र महासभा का समर्थन प्राप्त हुआ। इस पहल का उद्देश्य बाजरा पर प्रकाश डालना और उन्हें विश्व भूख के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे लाना है।

बाजरे की खेती को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की सोच - इस साल की शुरुआत में फालू की ट्विटर घोषणा में इस गीत को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में वर्णित किया गया था, जो किसानों के बीच बाजरा की खेती को प्रोत्साहित करने और भूख के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में योगदान देने के लिए तैयार किया गया था। पोस्ट में इस पहल के वैश्विक महत्व पर जोर देते हुए संयुक्त राष्ट्र द्वारा चालू वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने पर भी प्रकाश डाला गया।

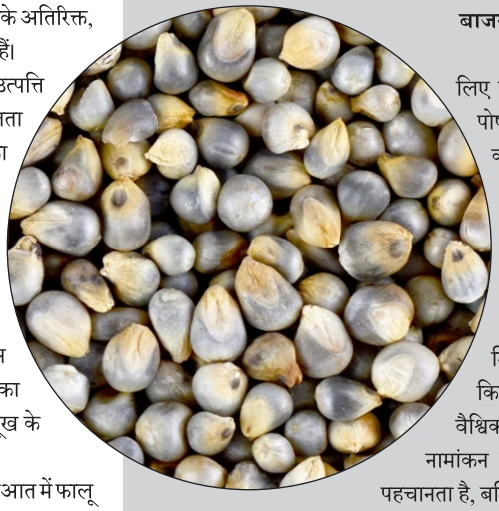

"एबंडेंस इन मिलेट्स" में फालू (फाल्गुनी शाह) और गौरव शाह ने अपनी आवाज दी है, जिन्होंने रचना और गीत की जिम्मेदारी भी संभाली है। रचनात्मक टीम में केन्या ऑटी, ग्रेग गोंजालेज और सौम्या चटर्जी शामिल हैं, साथ ही ऑटी संगीत वीडियो का निर्माण भी कर रहे हैं। वीडियो, जो भारत में बाजरा की खेती को दर्शाता है, एक मार्मिक दृश्य प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है कि कैसे यह साधारण अनाज भूख के खिलाफ एक महत्वपूर्ण हथियार हो सकता है।

बाजरा उपभोग: एक स्वास्थ्य क्रांति

अपने कृषि प्रभाव से परे, यह गीत सभी के लिए बाजरा की खपत को बढ़ावा देता है, इसके पोषण संबंधी लाभों और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने की क्षमता के बारे में बताता है। गीत में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के उद्धरणों को शामिल करने से संदेश को महत्व मिलता है, क्योंकि वह देश के किसानों के लिए सकारात्मक परिणामों पर जोर देते हुए, हमारी जीवनशैली में बाजरा के एकीकरण की वकालत करते हैं। "एबंडेंस इन मिलेट्स" संगीत की सीमाओं को पार करता है, किसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने वैश्विक संगीत मंच का उपयोग करता है। ग्रैमी नामांकन न केवल गीत की कलात्मक योग्यता को पहचानता है, बल्कि बाजरा के बारे में जागरूकता फैलाने और दुनिया भर में भूख कम करने की उनकी क्षमता में इसकी भूमिका को भी स्वीकार करता है। जैसा कि दुनिया 2024 ग्रैमी अवार्ड्स की धुन पर है, "एबंडेंस इन मिलेट्स" आवश्यक संदेश देने और वैश्विक स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने में संगीत की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है।

पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत का उदय, पहली बार 4 ट्रिलियन डॉलर के पार हुई देश की जीडीपी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। आज भारत हर मोर्चे पर नए-नए रिकार्ड बना रहा है। 18 नवंबर 2023 का दिन भी भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आजादी के बाद भारत की GDP पहली बार 4 ट्रिलियन डॉलर के पार निकल गई है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। यह 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पाने की दिशा में मील का पत्थर भी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की जीडीपी में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है।

2021 में भारत की जीडीपी 3.2 ट्रिलियन डॉलर थी, 2022 में यह बढ़कर 3.6 ट्रिलियन डॉलर हो गई और 2023 में यह बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर हो गई। अब जापान को 4.4 ट्रिलियन डॉलर और जर्मनी को 4.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ पछाड़कर भारत वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश बनने की ओर अग्रसर है। तिरंगे की लहर जारी है। देश की इस तरक्की के लिए सोशल मीडिया पर प्रधानंमत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी जा रही है।

भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बेहद करीब

जीडीपी लाइव के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने यह मुकाम 18 नवंबर की रात को हासिल किया। 18 नवंबर 2023 को रात करीब साढ़े 10 बजे भारत की जीडीपी का साइज पहली बार 4 ट्रिलियन डॉलर के पार निकल गया। अब भारत इसके साथ ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बेहद करीब पहुंच गया है। चौथे पायदान पर मौजूद जर्मनी और भारत की जीडीपी के बीच का अंतर अब बहुत कम बचा है।

भारत से आगे दुनिया की चार बड़ी अर्थव्यवस्थाएं

अभी अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था का मौजूदा आकार 26.7 ट्रिलियन डॉलर है। उसके बाद 19.24 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। 4.39 ट्रिलियन डॉलर के साथ जापान तीसरे नंबर पर है, जबकि जर्मनी 4.28 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ चौथे स्थान पर है।

भारत ने पिछले साल यूके और फ्रांस को पछाड़ा था

भारत ने इससे पहले 2022 में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ा था, और दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था। अभी भारत की आर्थिक वृद्धि दर को देखें तो यह किसी भी अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में सबसे ज्यादा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.8 फीसदी रही. उससे पहले पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था 7.2 फीसदी की दर से आगे बढ़ी थी।

अब 2027 तक 5 ट्रिलियन का लक्ष्य

मोदी सरकार ने देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का खाका तैयार किया है। यह सरकार के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए न सिर्फ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, बल्कि भारत की जीडीपी का साइज 5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी इस तरह का अनुमान दे चुका है।

भारत की ग्रोथ रेट सबसे तेज

रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5 फीसदी रहने वाली है। भारत की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में 6.5 फीसदी की दर से, तीसरी तिमाही में 6 फीसदी की दर से और चौथी तिमाही में 5.7 फीसदी की दर से बढ़ने वाली है। वहीं आईएमएफ का अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2023 और 2024 में 6.3 फीसदी की दर से वृद्धि करने वाली है। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में भी भारत सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहने वाला है।

भारत के लिए यह वैश्विक गौरव का क्षण -

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक्स पर पोस्ट किया, 'भारत के लिए यह वैश्विक गौरव का क्षण है क्योंकि हमारी जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नए भारत का उदय। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व वास्तव में अद्वितीय है।'

खूबसूरती से प्रगति कर रहा हमारा नया भारत - महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस आर्थिक तरक्करी के लिए पीएम मोदी की जमकर तारफी की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट किया, गतिशील, दूरदर्शी नेतृत्व ऐसा दिखता है! खूबसूरती से प्रगति कर रहा हमारा नयाभारत ऐसा ही दिखता है! मेरे साथी भारतीयों को बधाई क्योंकि हमारा राष्ट्र 4 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के आंकड़े को पार कर गया है! आपको अधिक शक्ति, आपका अधिक सम्मान, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।'

आइए देखते हैं देश की अर्थव्यवस्था और विकास पर विभिन्न संस्थानों और रेटिंग एजेंसियों का क्या कहना है...

चालू वित्त वर्ष में 6.3 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था- विश्व बैंक - भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर विश्व बैंक ने मोदी सरकार पर एक बार फिर भरोसा जताया है। 9 अक्तूबर को जारी विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक निवेश और घरेलू मांग के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2023-24 में 6.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल की पृष्ठभूमि में भारत लगातार मजबूती दिखा रहा है। विश्व बैंक ने कहा कि दक्षिण एशिया में इस साल 5.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान है। विश्व बैंक के उपाध्यक्ष (दक्षिण एशिया क्षेत्र) मार्टिन रायसर के मुताबिक पहली नजर में दक्षिण एशिया वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उज्ज्वल स्थान है। विश्व बैंक का अनुमान है कि यह क्षेत्र अगले कुछ वर्षों में किसी भी अन्य विकासशील देश क्षेत्र की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ेगा।

वित्त वर्ष 2023-24 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था-विश्व बैंक - विश्व बैंक ने इससे पहले भी कहा था कि भारत सबसे बड़े उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सकल और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दोनों के मामले में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। विश्व बैंक ने इसके पहले की रिपोर्ट में भी कहा था कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत रहेगी।

विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावनाओं पर रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उभरती हुई प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में भारत कुल मिलाकर और प्रति व्यक्ति जीडीपी दोनों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। विश्व बैंक के अनुसार भारत में निजी उपभोग और निवेश में अप्रत्याशित जुझारूपन देखने को मिल रहा है। साथ ही सेवाओं की वृद्धि भी मजबूत है। रॉयटर्स पोल के अनुसार, मार्च 2024 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 6.2 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।

‘भारत आटा’, देशभर में 2 हजार आउटलेट पर मिलेगा बाजार से काफी सस्ता आटा

देश में इस समय त्योहार का सीजन चल रहा है। दशहरा बीतने के बाद अब उजाले और समृद्धि का पर्व दिवाली आ रही है। इसको लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इसी बीच मोदी सरकार ने दिवाली से पहले देशवासियों को एक बड़ा गिफ्ट दिया है। 80 करोड़ लोगों को पांच साल तक मुफ्त राशन देने की घोषणा के बाद मोदी सरकार ने भारत ब्रांड का आटा लॉन्च किया है। सोमवार (06 नवंबर, 2023) को दिल्ली में कर्त्तव्य पथ पर लॉन्चिंग के मौके पर लोगों को इसके पैकेट बांटे गए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आटे के 100 वितरण वाहनों (मोबाइल वैन) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद मोदी सरकार देशभर में खोले गए दो हजार आउटलेट पर 27.50 रुपये प्रति किलो की कीमत पर ‘भारत आटा’ उपलब्ध कराएगी। इसका असर बाजार में आटे की कीमत पर भी पड़ेगा।

10 और 30 किलोग्राम के पैक में होगी ‘भारत आटा’ की बिक्री - ‘भारत आटा’ को 10 किलोग्राम और 30 किलोग्राम के पैक में उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इसे देशभर में 800 मोबाइल वैन और केंद्रीय भंडार, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएएफइडी), नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनसीसीएफ), सफल, मदर डेयरी और अन्य सहकारी संस्थानों के जरिए बेचा जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि आटे की बिक्री के लिए ढ़ाई लाख मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन विभिन्न सरकारी एजेंसियों को किया गया है। भारत ब्रांड आटा की खुदरा बिक्री शुरू होने से बाजार में सस्ती दरों पर आपूर्ति बढ़ेगी और बाजार में आटे की कीमत में कमी आने की उम्मीद है। पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार के दखल के चलते जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर नकेल कसने में मदद मिली है।

बाजार से काफी सस्ते दाम पर मिलेगा ‘भारत आटा’ - बाजार में जहां ब्रांडेड आटा 40 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है, वहीं नॉन-ब्रांडेड आटे की खुदरा कीमत 30 से 40 रुपये किलो हैं। ब्रांडेड आटा में शामिल आशीर्वाद आटा (41.50), सिल्वर कॉइन (37.50), फॉर्च्यून आटा(44.00), अन्नपूर्णा आटा (59.60) और नेचर फ्रेश आटा (42.00) प्रति किलोग्राम की कीमत पर बिक रहा है। मोदी सरकार ने रिटेल मार्केट में गेहूं की कीमतों में उछाल के बाद ओपेन मार्केट सेल स्कीम के तहत मार्च 2024 तक 101.5 लाख टन गेहूं अपने स्टॉक से बेचने का फैसला किया है। पिछले साल सरकार ने 57 लाख टन गेहूं बेचा था। अगर जरुरत पड़ी तो सरकार मार्च 2024 तक 25 लाख टन और गेहूं बाजार में बेच सकती है।

किफायती दम पर मिल रहा है आटा, दाल और प्याज - गौरतलब है कि फरवरी 2023 में मोदी सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना के तहत कुछ दुकानों में इन सहकारी समितियों के माध्मय से 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम पर 18,000 टन ‘भारत आटा’ की प्रायोगिक बिक्री की थी। इससे पहले मोदी सरकार अपने फिजीकल या खुदरा सरकारी दुकानों के माध्यम से भारत दाल (चना दाल) को 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 किलो पैक में 55 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रही है। प्याज भी 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच जा रहा है। अब उपभोक्ताओं को आटा, दाल और प्याज उचित और किफायती दम पर मिल रहा है।

खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कई कदम- मोदी सरकार ने खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर बेसिक शुल्क 2.5 प्रतिशत घटाकर शुन्य कर दिया है।

इन तेलों पर कृषि-उपकर 20 से घटाकर 5 प्रतिशत किया है। यह शुल्क संरचना 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दी गई है।

देश में रोज बढ़ रही UPI यूजर्स की संख्या

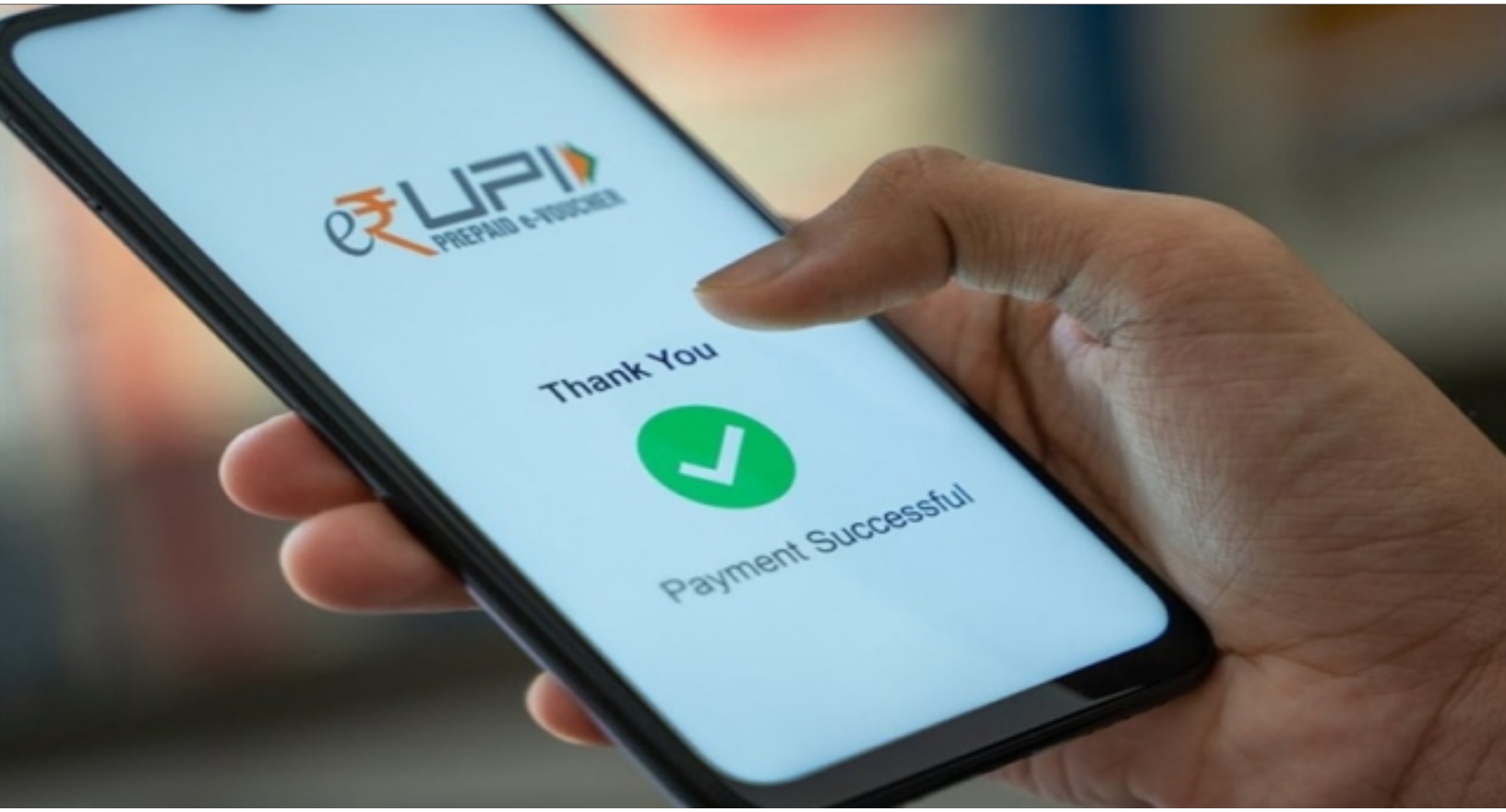

मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की नीति के कारण देश भर में लोग तेजी से यूपीआई को अपना रहे है। इससे लोगों को भुगतान के लिए अपने पास नकदी रखने की झंझट से भी मुक्ति मिल रही है। यूपीआई की तरह अक्टूबर में IMPS के जरिए ट्रांजेक्शन में तेजी आई है। अक्टूबर 2023 में 49.3 करोड़ ट्रांजेक्शन के जरिए 5.38 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया है। जबकि सितंबर में 47.3 करोड़ ट्रांजेक्शन के जरिए 5.07 लाख करोड़ रुपये और अगस्त 2023 में 48.9 करोड़ ट्रांजेक्शन से 5.14 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल विजन के कारण आज देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के जरिए ट्रांजेक्शन लगातार बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब अगस्त 2016 में UPI को लॉन्च किया था तब समूचे विपक्ष ने इसका माखौल उड़ाया था। वित्त मंत्री रह चुके कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने तो संसद में डिजिटल पेमेंट का मजाक उड़ाया था। आज डिजिटल पेमेंट सारे रिकार्ड तोड़ रही है। यह लगातार तीसरा महीना है जब यूपीआई लेनदेन की संख्या 1000 करोड़ के पार गई है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के मुताबिक, अक्टूबर 2023 में कुल 1141 करोड़ यूपीआई ट्रांजेक्शन के जरिए 17.16 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया। जबकि सितंबर 2023 में 1056 करोड़ ट्रांजेक्शन के माध्यम से 15.80 लाख करोड़ रुपये की राशि का लेनदेन किया गया और अगस्त 2023 में 1058 करोड़ ट्रांजेक्शन के जरिए कुल 15.76 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन किए गए।

क्यूआर कोड ने दिया अहम योगदान

क्यूआर के आ जाने के बाद यूपीआई ट्रांजेक्शन में और भी ज्यादा तेजी से इजाफा आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपीआई के 330 लाख से भी ज्यादा यूनीक यूजर्स हैं और लगभग 70 लाख दुकानदारों ने 356 लाख क्यूआर कोड को लगाया है। इसके अलावा PhonePe, Google Pay, Paytm, और Amazon Pay जैसे UPI ऐप्स की वजह से इसका ट्रांजेक्शन बढ़ा है।

गांव में कैशलेस अर्थव्यवस्था के बारे में बात नहीं की जा सकती: पी. चिदंबरम

2017 की शुरुआत में मोदी सरकार के 'डिजिटल इंडिया' अभियान की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने संसद में डिजिटल पेमेंट का मजाक उड़ाते हुए कहा था "आप लोग गांव जाइये और 10 रूपये की सब्ज़ी खरीदिये, वहां बिना मशीन, वाई-फाई, इंटरनेट के कैसे पेमेंट कर पाओगे।" चिदंबरम ने कहा था, "कोई किसी गांव में जाकर कैशलेस अर्थव्यवस्था के बारे में बात नहीं कर सकता। आप वहां जाएं तो लोग पूछेंगे कि 'क्या है डिजिटल?'।" चिदंबरम ने कहा था झूठ बोलकर बचना बहुत मुश्किल है। अब देशवासियों ने गांव-गांव में डिजिटल पेमेंट करके दिखा दिया है तो यह साफ हो गया है कि झूठ चिदंबरम बोल रहे थे और वह देश को गुमराह कर रहे थे।

भारत-बांग्लादेश सहयोग की सफलता

बांग्लादेश की प्रधान मंत्री के साथ विकास परियोजनाओं के संयुक्त वर्चुअल उद्घाटन पर प्रधान मंत्री का वक्तव्य

प्रधान मंत्री शेख हसीना जी, नमस्कार! ये बहुत खुशी की बात है, कि हम एक बार फिर, भारत-बांग्लादेश सहयोग की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं।हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं।

पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था।

हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए, दशकों से लंबित, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया।

और, मैरीटाइम बाउन्ड्री को भी सुलझाया।

दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमने infrastructure और connectivity के विकास पर विशेष बल दिया।

पिछले 9 वर्षों में तीन नई बस सेवाएं शुरू की की गई हैं।

इससे ढाका, अगरतला, शिलांग, गुवाहाटी, और कोलकता को आपस में जोड़ा गया।

पिछले 9 वर्षों में तीन नई रेल सेवाएं भी शुरू की गई।

2020 से तो, भारत-बांग्लादेश के बीच कंटेनर और पार्सल ट्रेनें भी चल रही हैं।

पिछले 9 वर्षों में Inland Waterways को passenger और goods के यातायात के लिए विकसित किया गया।

इसी रास्ते से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए exports का रास्ता खुल गया है।

विश्व का सबसे बड़ा क्रूज़ – गंगा विलास - भारत और बांगलादेश के बीच शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिला है।

पिछले 9 वर्षों में चिटागोंग और मोंगला पोर्ट के रास्ते से भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को जोड़ा गया है।

हमारे कनेक्टिविटी initiatives ने, Covid महामारी के दौरान लाइफ-लाइन का काम किया।

"ऑक्सीजन एक्सप्रेस" ने चार हज़ार टन से ज्यादा लिक्विड medical ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंचाई।

पिछले 9 सालों में, भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर, चार नए इमिग्रेशन चेक पोस्ट खोले गए हैं।

और, पिछले 9 वर्षों में हमारा आपसी व्यापार लगभग तीन गुना हो गया है।

Friends,

इन 9 वर्षों की यात्रा में, आज "अखौरा-अगरतला रेल लिंक" उसका उद्घाटन भी एक ऐतिहासिक पल है।

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बांग्लादेश का ये पहला रेल लिंक है। त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ लिबरेशन स्ट्रगल के समय से गहरा नाता रहा है।

इस लिंक के माध्यम से, पूर्वोत्तर भारत के राज्य, बांग्लादेश के ports से भी जुड़ेंगे। "खुलना - मोंगला पोर्ट रेल लाइन"

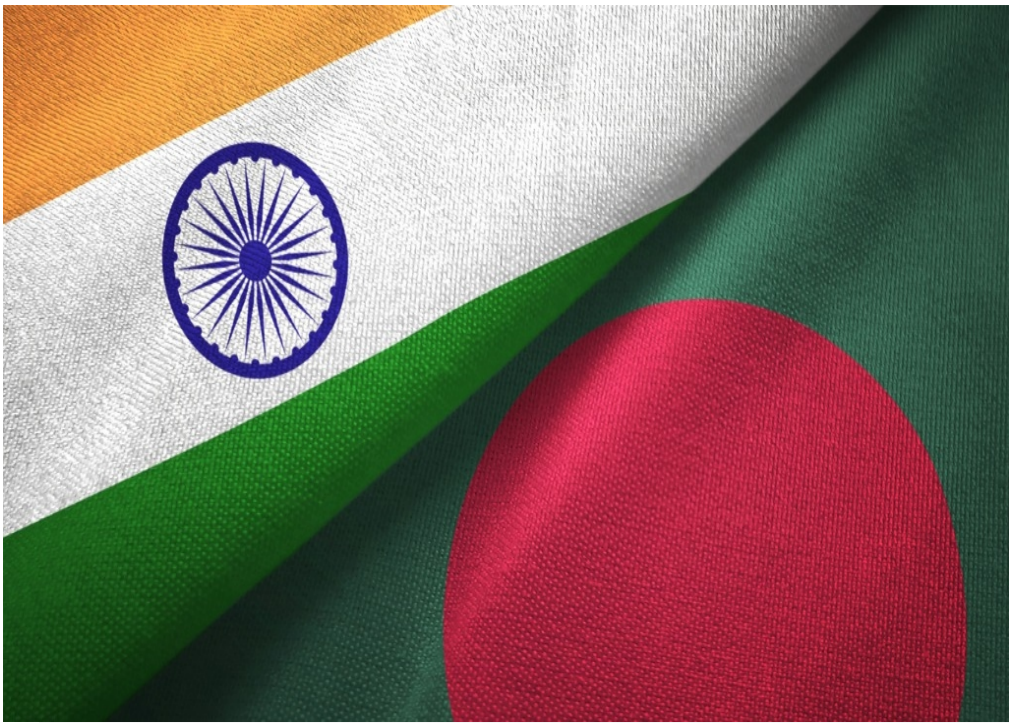

इसके बनने से अब बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट, रेल के रास्ते ढाका और कोलकाता ट्रेड सेंटर्स से जुड़ गया है। मुझे खुशी है कि आज हमने "मैत्री थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट" के दूसरे यूनिट का उद्घाटन किया। पिछले 9 वर्षों में, हमारे पावर और एनर्जी सहयोग में यह एक नई कड़ी है।

2015 से, 160 मेगावाट बिजली, त्रिपुरा से बांग्लादेश जा रही है। पिछले वर्ष, हमने मैत्री थर्मल पॉवर प्लांट के पहले यूनिट का अनावरण किया था। इसी वर्ष, मार्च में, दोनों देशों के बीच पहली क्रॉस बार्डर हाई स्पीड डीजल पाईपलाइन का उद्घाटन किया गया। हमारे आपसी सहयोग से बांग्लादेश की एनर्जी सिक्यूरिटी को बल मिला है।

ऊर्जा क्षेत्र में बांग्लादेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। यही नहीं, इस वर्ष सब-रिजनल कनेक्टिविटी के लिए भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच बिजली के आदान-प्रदान पर भी सहमति बनी है। Friends, हमने "सबका साथ, सबका विकास" की हमारी approach को बांग्लादेश जैसे अपने निकटतम पड़ोसी मित्र के लिए भी प्रासंगिक माना है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा development पार्टनर होने पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। पिछले 9 वर्षों में, विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए लगभग 10 बिलियन डॉलर की सहायता दी जा रही है।

हमारे achievements की लिस्ट इतनी बड़ी है कि, उसकी व्याख्या करते हुए पूरा दिन निकल जाए।

हमने साथ मिल कर पुराने, रुके हुए काम तो पूरे किए ही हैं।

लेकिन आज के कार्यक्रम की एक और विशेषता है। आज जिन तीन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है,

उनका निर्णय भी हमने लिया था, और इन्हें लोगों को समर्पित करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला है।

Friends, हमारे संयुक्त प्रयासों की सफलता के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ। कुछ सप्ताह पहले, वे G-20 समिट में विशेष अतिथि के रूप में भी शामिल हुई; हमें उनका स्वागत, सम्मान करने का अवसर मिला, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। Excellency,आपके 'Smart बांग्लादेश' को आगे बढ़ाने में भारत पूरा सहयोग देता रहेगा। मुझे खुशी है कि बांग्लादेश के 12 जिलों में 12 आई-टी पार्क्स बनाने में भारत सहयोग दे रहा है। Fintech के क्षेत्र में, दोनों देशों के पेमेंट गेटवेस को जोड़ने के लिए भी सहमति बनी है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से, बंगबंधु के 'सोनार बांग्लादेश' का विजन साकार होगा। एक बार फिर, इस आयोजन में शामिल होने के लिए, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद!

सर्दियों का सुपरफूड है बाजरा

आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सीजन के हिसाब से भोजन करना चाहिए। यानि ऋतु फल, सब्जियां और अन्न को अपने भोजन का हिस्सा बनाएं। ठंड में ऐसे फल सब्जियां आते हैं जो शरीर को गर्म रखते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। सर्दियों में आपको मिलेट्स यानि बाजरा जरूर खाना चाहिए। बाजरा की रोटी खाने में स्वादिष्ट लगती है और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। सर्दियों में बाजरा की रोटी और सरसों का साग खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। पंजाब से लेकर हरियाणा और यूपी में बाजरा काफी खाया जाता है। फाइबर से भरपूर बाजरा प्रोटीन, विटामिन और मिनरल का अच्छा सोर्स है। बाजारा खाने से डायबिटीज और वजन दोनों कंट्रोल रहता है। जानिए इसके फायदे।

बाजरा में कौन से पोषकतत्व पाए जाते हैं

सबसे पहले जान लें कि बाजरा में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। बाजरा में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। डाइट्री फाइबर, प्रोटीन और विटामिन भी भरपूर होता है। बाजरा आयरन और जिंक का अच्छा सोर्स है। इसके सेवन से शरीर को विटामिन बी3, विटामिन बी6 और विटामिन बी9 मिलता है।

बाजरा से क्या क्या बनता है

बाजरा से आप कई तरह की डिश बनाकर खा सकते हैं। आप गेहूं के आटे में बाजरा मिक्स करके खाने में शामिल कर सकते हैं। आप सिर्फ बाजरा की ही रोटी बनाकर खा सकते हैं। बाजरा के पराठे और मीठी टिक्की भी बनती है। बाजरा की खिचड़ी भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप चाहें तो बाजरा को उबालकर स्पाउट्स की तरह खा सकते हैं।

बाजरा खाने के फायदे

हार्ट अटैक से बचाए- आजकल हार्ट अटैक के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। खासतौर से सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा काफी बढ़ जाता है। ऐसे में दिल के मरीज को बाजरा का सेवन करना चाहिए। इसमें काफी मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है जो हार्ट के लिए अच्छा होता है।

डायबिटीज को कंट्रोल करे- डायबिटीज के मरीज को खाने में आटा सोच समझकर खाना चाहिए। डायबिटीज में बाजरा का आटा बहुत फायदेमंद होता है। बाजरे की रोटी खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। क्योंकि इसमें फाइबर काफी होता है। बाजरा खाने से कब्ज से भी राहत मिलती है।

हाई ब्लड प्रेशर में फायदा- हाइपरटेंशन के शिकार लोगों को भी बाजरा के आटे की रोटी खानी चाहिए। ये काफी फायदा करती हैं। बाजरा में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है।

बैड कोलेस्टॉल घटाता है- आजकल फिटनेस फ्रीक लोग बाजरा यानि मिलेट्स का सेवन करने लगे हैं। पहले बाजरा गांव- देहात के लोग ज्यादा खाते थे। यही वजह है कि उनका शरीर बीमारियों से दूर रहता था। बाजरा खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा रहता है उन्हें बाजरा अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए।

वजन घटाता है बाजरा- बाजरा की रोटी या खिचड़ी खाने से मोटापा कम होता है। बाजरा में फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है जिससे लंबे समय तक पेट भरा रहता है। बाजरा खाने से वजन घटाने में मदद मिलती है। इसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो वेट लॉस में हेल्प करता है।

Lok Shakti

NATIONALISM

OPENION

REMARK

DISCOVERY

ENLIGHTEN

ANALYSIS

KNOWLEDGE

POLITICS

IDEOLOGY

Access Lok Shakti online for free.

Now, read Lok Shakti on your smart phone instantly.
Point your phone's scanner on the
code and align it in the frame.
You will be guided instantly to www.lokshakti.in.

All Rights Reserved
Terms & Conditions Apply.
Lok Shakti exclusively holds all the rights to cancel the subscription without any prior Notice.
If you wish to Unsubscribe, let us know at the official contact no.
In case of any Dispute, Jurisdiction area will be Raipur

Owner, Printer, Publisher & Editor- Premendra Agrawal, Published from 5/756, Desh Bandhu Press Road, Behind Sindhi School, Raipur (C.G.) - 492001
& Printed at Commercial Services, Ramsagarpara, Raipur (C.G.)